-: सुविचार :-

''जीवन में जो भी प्राणी भजन- सुमिरन नहीं करता उसे दुख के कांटे चुभते ही रहेंगे।''

कलम लोक

Website : www.kalamlok.com

कश्मीर घाटी में वोटिंग के टूटे...

वर्ष 07 | अंक 345 | बक्सर, शनिवार 29 जून 2024 | पृष्ठ - 8 | मूल्य - 2 रूपये

हाईकमान तक शिकायत रोकने फिर सेटिंग की तैयारी में भूपेश और छुटभैया नेता

भूपेश को सत्ता के नशे में डूबा कर सलाहकारों ने बना दिया था धृतराष्ट

सत्ता के घमंड में चूर सलाहकार तय करते थे कि कौन मिलेगा भूपेश से

अप्रत्याशित जीत को कांग्रेसियों के अहंकार ने अप्रत्याशित हार में बदल दिया

सत्ता पाते ही मुखिया ने उन सभी को दरकिनार कर दिया जो उसके लिए लड़े मरे

2023 के विधानसभा चुनाव में सभी असंतुष्टों ने जमकर बदला लिया हरा कर

भूपेश पर गुस्सा निकालने कांग्रेसियों ने कांग्रेस को ही हरा दिया

क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हाईकमान को भूपेश की सच्चाईयां से अवगत कराने हौसला करेगी

क्या सच्चाईयों से अवगत होने के बाद हाईकमान भूपेश और छुटभइये नेताओं पर कार्रवाई करेगा

रायपुर। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेसियों के लिए प्रत्याशित ही रहे। प्रत्याशित नतीजे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस भी पार्टी में सरकार बनने के बाद जमीनी कार्यकर्ताओं को हासिये पर डाल दिया जाता है या संगठन को कमजोर कर सिर्फ सत्ता और सत्ता के ईद-गिर्द रहने वाले चंद सलाहकारों और चाटुकारों को पावर सेंटर में लाया जाता है वहां सरकार परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है । ऐसा ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के साथ हुआ और आश्चर्य की बात यह रही कि इस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को यह कुर्सी तब नसीब हुई जब उन्होंने सरकार बनने से पहले लगातार 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से संगठन को काफी मजबूत दी और लगातार भाजपा सरकार को सड़क से सदन तक गिरने में कामयाबी पाई। पदयात्रा के अच्छे सलाहकारों और पत्रकारों की सलाह पर अमल किया। नसबंदी कांड, आंख फोड़वा कांड, नान घोटाला जैसे मुद्दों को उछाल कर जनता का समर्थन भी हासिल की, पर यही भूपेश बघेल जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन की मजबूती के लिए सदा तत्पर रहते थे । रोज दोपहर बाद कांग्रेस भवन में बैठकर अच्छे सलाहकार और पत्रकारों से सलाह कार्यक्रम करते थे सरकार के मुख्य बनते ही उनका एक नया रूप प्रदेश की जनता के सामने आया। उन्होंने संगठन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया निगम मंडल की नियुक्ति में मनमानी की। कभी जनदर्शन नहीं लगाया। चाटुकार और गलत सलाहकारों से घिर गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी लगातार अपमानित किया। संगठन के पदाधिकारी का भी कोई काम नहीं किया। जिन पत्रकारों और अच्छे सलाहकारों और संगठन के मजबूत कार्यकर्ताओं की सलाह और मेहनत से वे इस कुर्सी तक पहुंचे वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे बंद कर दिए।

पूरी तरह सरकार मुट्ठी भर उनके गलत सलाहकार और 4-5 ब्यूरोकेट्स चलाने लगे और नतीजा यह हुआ कि अकेले आदमी के घमंड अहंकार और गलत सलहकारों की वजह से 11 विधायकों वाली मजबूत सरकार औंधे मुंह जा गिरी और प्रदेश बनने के बाद हुए 4 विधानसभा चुनाव में अपने सबसे कमजोर प्रदर्शन के साथ 35 विधायकों वाली विपक्षी पार्टी बनकर रह गई। जिस प्रदेश में कांग्रेस के 29 विधायक आदिवासी समाज के थे उसकी लगातार अपेक्षा होती रही। वरिष्ठ नेताओं की अवेलहना होती रही, कार्यकर्ताओं के निजी कार्य भी नहीं हुए। ढाई साल वाला मुद्दा भी गरमाया रहा। संगठन अध्यक्ष मोहन मरकाम की भी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी मुख्यमंत्री समर्थकों ने संगठन को दरकिनार किया। ऊपर से कुछ पत्रकारों को प्रताड़ित कर सरकार बदनाम होने लगी। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की लगातार शिकायत आने लगी और सरकार कोयला घोटाला, सट्टा घोटाला, परिवहन विभाग की वसूली, अवैध शराब घोटाला जैसे कई मामलों में बदनाम होती चली गई। रामगोपाल अग्रवाल, सौम्या चौरसिया, गिरीश देवांगन, सूर्यकान्त तिवारी विनोद वर्मा की भी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देने लग गई। यही लोग तय करने लगे मुख्यमंत्री से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। मीडिया हाउस को निर्देश जाने लगे कि क्या छपेगा क्या नहीं। दमनकारी फैसले होने लगे और मजे की बात यह है कि ये सभी बातें प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता था कि कहां-कहां से कलेक्शन हो रहा है कौन कर रहा है और वह कलेक्शन कहां जा रहा है संगठन भी निराशा और हताशा में होने जा रहा था। क्योंकि तमाम बातों को हाईकमान तक पहुंचाने के बाद भी हाईकमान के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार एआईसीसी के लिए एटीएम का कार्य कर रही थी और सरकार जाना उसी दिन तय हो गया जिस दिन सरकार का मुखिया बदलने की बजाए मोहन मरकाम को ठीक चुनाव से पहले बेवजह हटा दिया और टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बना दिया गया। उसमें सरगुजा और बस्तर भी नाराज हो गया। कार्यकर्ता पहले ही नाराज बैठा था और इन सब से मिलकर चुनाव में कांग्रेस को धूल चटा दी और कांग्रेस बस्तर, सरगुजा में पूरी तरह साफ हो गई। चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं की भड़ास निकालने लगी और वे सब परिणामों की समीक्षा की मांग करने लगे फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आ गए लोकसभा चुनाव और यह चुनाव कांग्रेस की युवराज के प्रतिष्ठा से चुनाव जुड़े थे। प्रदेश में 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी पर हाईकमान ने फिर गलती की और जिस भूपेश बघेल के कारण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण फिर से उन्हें को दे दिया गया। और जिस तरह इनकी सरकार में दुर्ग जिले के चार मंत्री थे और सब चुनाव हार गए। उसी तरह लोकसभा में दुर्ग के 4 लोगों को टिकट मिला और चारों चुनाव हार गए और परिणाम आशा अनुसार जो आने थे वही आए। वो तो चरणदास महंत ने अपने पुराने अनुभव से चुनाव लड़ा और पार्टी की इज्जत बचा पाए। वरना सभी 11 सीटों पर हार तय थी। अब चुकी है चुनाव राहुल गांधी से जुड़े थे तो पुन: समीक्षा की मांग उठने लगी। अब अंतत: समीक्षा बैठक होने जा रही है। और समीक्षा करने आ रहे कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता वीरप्पन मोइली और हरीश चौधरी सभी लोकसभा सीटों के परिणामों की समीक्षा होगी। 28 जून को रायपुर, महासमुंद की, रायपुर में 29 जून को बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर और सरगुजा लोकसभा की बिलासपुर में 30 जून के कांकेर, बस्तर लोकसभा के कांकेर में 1 जुलाई को दुर्ग, राजनांदगांव लोकसभा की समीक्षा, रायपुर के राजीव भवन में अब देखना ये होगा कि ये सच में हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा कर पार्टी परिणाम के दोषियों की जानकारी हाईकमान को देकर पार्टी की मजबूती के लिए अमूल चूक परिवर्तन कर पार्टी के ईमानदार मजबूत और जुझारू कार्यकर्ताओं को मौका देगी, कि ये अपनी पुरानी परिपाटी की तरह समीक्षा का ढोंग कर पुन: कार्यकर्ताओं को ठगा सा महसूस कराएंगी। गौरतलब देखना यह होगा कि क्या जिन परिणाम के कारण कांग्रेस को बच्चा-बच्चा जानता है उन्हें अपनी बात पर्यवेक्षकों के सामने रखने का अवसर मिलेगा। क्या उन कारणों के बारे में जानकारी लेकर पर्यवेक्षक इमानदारी से अपनी रिपोर्ट से हाई कमान तक अवगत करा पाएंगे कि पुणे फिर से एक बार समीक्षा का बहाना कर कार्यकर्ताओं को ठगा जाएगा।

सीएम साय के जनदर्शन कार्यक्रम का हुआ आगाज, प्रत्येक गुरुवार जनता के नाम

वर्षों बाद आम लोगों के लिए फिर खुले मुख्यमंत्री के दरवाजे

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार का पहला जनदर्शन कार्यक्रम गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा।

आम नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार को बने छह माह हुए हैं। इस दौरान लोगों से लगातार मुलाकातें हुई है, सभी से मिलने की मैं कोशिश करता रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस होती रही, जो केवल आम नागरिकों से मुलाकात के लिए हो। पूर्व में डॉ. रमन सिंह की सरकार के समय जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था। अब उसी कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आज फिर से शुरू किया है। जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक गुरूवार को आयोजित होगा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत,

सचिव पी. दयानंद, जनसम्पर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव सहित सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, रायपुर जिले के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरूवार को पूर्वान्ह 11 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया

जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग द्वारा समय-सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देंगे।

बारिश के बीच दिल्ली के बड़ा हादसा, कई गाड़ियां दबी

IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-1 की छत गिरी, 1 की मौत

नई दिल्ली (ए/नेट डेस्क)। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा गिर गया। जिसकी चपेट में आकर कई कारें दब गईं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि छह लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

दिल्ली फायर ब्रिगेट के एक अधिकारी ने बताया, सुबह करीब 5.30 बजे हमें दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत गिरने की सूचना मिली। दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई भारी बारिश के बीच यह हादसा हुआ। इसी बीच, दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव देखा गया। साउथ दिल्ली में गोविंदपुरी और नोएडा सेक्टर 95 में जलभराव देखने को मिला। दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं आईटीओ पर बारिश की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई दिखी।

टर्मिनल-1 से डिपार्चर सस्पेंड : घटना को लेकर डायल के प्रवक्ता ने कहा, आज सुबह से ही भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पुराने डिपार्चर फोरकोर्ट में कैनोपी का एक हिस्सा सुबह 5 बजे के आसपास नीचे गिर गया। हादसे में लोगों के घायल होने की खबर है। इमरजेंसी कर्मचारी प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सा सहायता देने का काम कर रहे हैं। इस घटना की वजह से, टर्मिनल-1 से सभी डिपार्चर अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए गए हैं। एहतियातन चेक-इन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। हम इस परेशानी के लिए खेद व्यक्त करते हैं और किसी भी असुविधा के लिए माफी मांगते हैं।

मंत्री कर रहे मॉनिटर : एयरपोर्ट पर हुए हादसे की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने एक्स पर लिखा, मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली एयरपोर्ट के टी-1 पर छत गिरने की घटना की निगरानी कर रहा हूं। घटनास्थल पर बचाव दल काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइनों को टी-1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है।

दिल्ली में बृजमोहन ने ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन से की भेंट

रायपुर। नई दिल्ली प्रवास के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन से सौजन्य भेंट एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। व्यापार, शिक्षा, खेल, पर्यटन एवं संस्कृति समेत अनेक क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख सहयोगी हैं। जिसका आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिल सकता है।

अपने 𝕏 पोस्ट में MP बृजमोहन अग्रवाल ने बताया, नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन जी से सौजन्य भेंट एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। व्यापार, शिक्षा, खेल, पर्यटन एवं संस्कृति समेत अनेक क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख सहयोगी हैं। जिसका आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिल सकता है।

अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना

जम्मू (ए/नेट डेस्क)। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार (28 जून) की सुबह 4.30 बजे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर जम्मू के बेस कैंप से रवाना किया। भक्तों का यह जत्था दोपहर 2 बजे दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और मध्य कश्मीर के बालटाल पहुंचेगा।

एलजी सिन्हा ने एक दिन पहले ही जम्मू में यात्री निवास भवन का दौरा किया था। इससे पहले एलजी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम बेस कैंप भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सुरक्षा संबंधी बैठक की अध्यक्षता की थी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ

श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

साधुओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर : 52 दिवसीय तीर्थयात्रा 29 जून को दो मार्गों - अनंतनाग में पारंपरिक 48 किमी लंबे नुनवान-पहलगाम मार्ग और गांदरबल में 14 किमी छोटे, लेकिन कठिन बालटाल मार्ग- से शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक शहर के शालीमार इलाके में अपंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण केंद्र स्थापित किया गया है, वहीं पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर परिसर में साधुओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष शिविर लगाया गया है।

बेस कैंप में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ : अधिकारियों के मुताबिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1600 तीर्थयात्री कश्मीर की अपनी आगे की यात्रा के लिए भगवती-नगर आधार शिविर पहुंचे। बेसकैंप में भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं सहित 800 से ज्यादा साधु पारंपरिक राम मंदिर और गीता भवन पहुंचे। यहां पहुंच रहे श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर, में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं।

पुणे-बैंगलोर नेशनल हाइवे पर भीषण हादसा, 13 की मौत

हावेरी (ए/नेट डेस्क)। कर्नाटक के हावेरी में भीषण

रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, हावेरी के बडगी में रोड पर खड़े वाहन में एक गाड़ी टकरा गई। यह दुर्घटना आज सुबह हावेरी जिले के बडगी तालुक में गुंडेनहल्ली क्रॉस के पास पुणे-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। रोड पर खड़ी लॉरी से टकराने के बाद यात्री गाड़ी पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में लोगों के शव मिले। दमकल विभाग के कर्मचारी गाड़ी में फंसे शवों को निकाल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि मृतक शिमोगा जिले के भद्रावती तालुक में होलेहोन्नूर के पास एम्मीहट्टी गांव के रहने वाले थे।

गंदगी में कैसा इलाज?

बिहार के 97 फीसदी सरकारी अस्पताल सफाई और हाईजीन में फेल

मुजफ्फरपुर (संवाददाता)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और समुचित इलाज के बड़े बड़े दावे करते है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सफाई और हाइजीन के मामले में राज्य के सरकारी अस्पताल बुरी तरह से फेल हो गये हैं। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना में सूबे के सिर्फ 2.4 प्रतिशत अस्पताल को ही 70 प्रतिशत से अधिक अंक आये हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है।

एन्क्वास के मानक पर भी अस्पताल खरे नहीं

सरकारी अस्पताल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस (एनक्वास) के मानक पर भी खरे नहीं हैं। इसके लिए भी कई बार अस्पतालों में पीयर टीम आई और खामियों को दूर करने के लिए कहा, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है।

सदर अस्पताल बार-बार हो रहा फेल

सदर अस्पताल बार-बार कायाकल्प योजना के मूल्यांकन में फेल हो जा रहा है। कायाकल्प के अलावा लक्ष्य प्रमाणीकरण में भी सदर अस्ताल जांच में फिसड्डी साबित हुआ है। पिछले दिनों लक्ष्य सर्टिफिकेट की जांच के लिए टीम आई थी। टीम ने अस्पताल के एमसीएच में कई कमियां उजागर कीं और इसे दुरुस्त करने को कहा। अभी पूरे जिले में सिर्फ एसकेएमसीएच के एमसीएच को लक्ष्य का सर्टिफिकेट मिला हुआ है।

कायाकल्प योजना के तहत बिहार के 10 हजार 952 अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया था, इनमें सिर्फ 301 अस्पतालों को 70 प्रतिशत से अधिक अंक मिले। मुजफ्फरपुर जिले के 578 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ नौ को 70 प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं। क्षेत्रीय अपर निदेशक (स्वास्थ्य) डॉ. ज्ञान शंकर ने बताया कि कायाकल्प योजना में बेहतर अंक लाने के लिए सभी सीएस को निर्देशित किया गया है। कहा है कि अविलंब सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक करें ताकि विभाग की बदनामी नहीं हो। कायाकल्प योजना में अस्पतालों में सफाई, हाइजीन के साथ मरीजों की संतुष्टि पर अंक दिये जाते हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम अस्पतालों का निरीक्षण करती है और मरीजों से भी बात करती है। निरीक्षण और मरीजों के फीडबैक के आधार पर टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। कायाकल्प की तैयारी के लिए कई बार अस्पतालों को राज्य स्तर से भी निर्देश दिया गया, इसके बाद भी कोई असर नहीं देखा गया और सरकारी अस्पताल इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं।

लोजपा के सांसदों से क्यों मिल रहे पीएम मोदी, चिराग से बोले- आपने खुद को साबित किया है

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने खुद को योग्य साबित किया है और अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। समाजवादी नेता रामविलास पासवान ने लोजपा का गठन किया था और उनके निधन के बाद पार्टी दो धड़ों में विभाजित हो गई थी।

एक धड़े का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री व रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में है। दोनों ही धड़े राजग के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत भाजपा ने लोजपा (रामविलास) को पांच सीट दी थीं, जबकि पशुपति पारस नीत पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। भाजपा पर अपनी पार्टी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए 'एक्स' पर लिखा, 'रामविलास पासवान जी मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जिनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मुझे बहुत याद आती है। मुझे खुशी है कि चिराग पासवान ने खुद को योग्य साबित किया है और रामविलास जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारी पार्टियां सार्वजनिक सेवा के लिए मजबूती से एक साथ हैं।' संसद का सत्र शुरु होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को जेडीयू के सांसदों से मोदी की मुलाकात हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की थी। मोदी ने बुधवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों से मुलाकात की थी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सराहना की थी। लोकसभा में तेदेपा के 16 सांसद हैं और वह भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है। लोकसभा में 12 सांसदों के साथ जद(यू) भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, जबकि लोजपा (रामविलास) के पांच सांसद हैं।

खबर-खास

बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन के शीशे टूटे; यात्री सहमे

पटना (संवाददाता)। बिहार में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। पटना से हावड़ा जा रही वंदे भारत ट्रेन पर शुक्रवार को शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके। इससे ट्रेन की खिड़की के शीशा टूट गए। अचानक हुए पथराव से ट्रेन में सवार यात्री भी डर गए। हालांकि, इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। ट्रेन पर पथराव की घटना मोकामा में हाथीदह जंक्शन और बड़हिया स्टेशन के बीच हुई।

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह पटना से हावड़ा के लिए ट्रेन नंबर 22348 वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई। मोकामा से आगे निकलने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके। बताया जा रहा है कि दो-तीन पत्थर ट्रेन की खिड़कियों पर लगे, जिससे शीशे दरक गए। पत्थर फेंके जाने से यात्री अचानक से डर भी गए थे। हालांकि, ट्रेन हावड़ा की ओर बढ़ती रही। आरपीएफ ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पथराव करने वाले शरारती तत्वों की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते अप्रैल में वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत पर सासाराम में करवंदिया स्टेशन के पास पत्थर फेंके गए थे। इससे पहले जनवरी महीने और पिछले साल भी वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं सामने आई थीं। बता दें कि पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत पिछले साल सिंतबर महीने में हुई थी। इस रूट की यह सबसे तेज ट्रेन है। पटना से हावड़ा की 530 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन महज साढ़े 6 घंटे में कवर करती है।

संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं नीतीश कुमार

पटना (संवाददाता)। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। नीतीश सरकार में मंत्री रहे संजय झा पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं और इसी हफ्ते उन्हें राज्यसभा में जदयू संसदीय दल का नेता बनाया गया है। नीतीश ने शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संजय झा को पार्टी में नंबर दो की जिम्मेदारी दी जा सकती है। नीतीश समेत जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। शनिवार की बैठक में जेडीयू के सभी सांसद, मंत्री, राज्यों के पार्टी चीफ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हिस्सा लेंगे। संजय झा ने नीतीश की एनडीए में वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई है।

जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। इससे पहले पिछले साल 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें ललन सिंह ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और खुद नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाली थी। इसके एक महीने बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में वापस आ गए थे। ठीक 6 महीने बाद फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पार्टी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मीटिंग से एक दिन पहले संजय झा को जेडीयू में अहम जिम्मेदारी देने की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में संजय झा के मंत्री बनने की अटकलें लगी थीं लेकिन पार्टी ने ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मौका दिया।

बिहार में 11 दिनों के अंदर पांचवां पुल गिरा, अब मधुबनी में ब्रिज हादसा; तेजस्वी यादव बोले- बूझो तो जानें

मधुबनी (संवाददाता)। बिहार में शुक्रवार को एक और पुल हादसा हो गया। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा बारिश के तेज बहाव में ढह गया। बीते 11 दिनों के भीतर बिहार में पुल गिरने की यह पांचवीं घटना है। इससे पहले किशनगंज, अररिया, पूर्वी चंपारण और सीवान में पुल गिर चुके हैं। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना भी साधा है।

जानकारी के मुताबिक मधुबनी में भूतही बलान नदी में निर्माणधीन पुल का बीम गिर गया। यह घटना मधेपुर प्रखंड के भेजा स्थित ललवारही टोला की है। यहां 25 मीटर की लंबाई में बीम एवं लोहे का स्ट्रक्चर अचानक धराशायी हो गया। इस पुल का निर्माण 2.98 करोड़ की लागत से हो रहा है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बीते 18 जून से शुरू हुआ। सबसे पहले अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल उद्घाटन से ठीक पहले भरभराकर गिर गया। इसके बाद 22 जून को सीवान के महाराजगंज में गंडक नहर पर बना पुल धंस गया। इसके तुरंत बाद पूर्वी चंपारण जिलेके अमवा में भी निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। एक दिन पहले गुरुवार को किशनगंज जिले में मरिया नदी पर बना 13 साल पुराना पुल तेज बहाव से धंस गया। बिहार में पुल गिरने की घटनाएं देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आए दिन हो रहे इन हादसों से निर्माण और मरम्मत कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में पांच पुल गिर चुके हैं। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए लोगों से कहा कि आपको यह पता है क्या, नहीं पता है तो बूझो तो जानें।

नीट पेपर लीक

सीबीआई को मनीष और आशुतोष की 5 दिन की रिमांड मिली, क्या है इनकी भूमिका?

पटना (संवाददाता)। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दो आरोपियों की रिमांड मिली है। पटना की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार उर्फ चिंटू को पांच दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। इन दोनों ने नीट पेपर लीक में सेटर की भूमिका निभाई थी। पटना के खेमनीचक स्थित जिस लर्न एंड प्ले स्कूल में नीट परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए थे, वहां छात्रों को ये ही दोनों लेकर पहुंचे थे। पूछताछ में सीबीआई इनसे पेपर लीक के और राज उगलवा सकती है।

पटना के सीबीआई विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक के आरोपी मनीष और आशुतोश की पांच दिन की रिमांड की अनुमति दी। इससे पहले सीबीआई दिल्ली के अधिकारी अपने वकील के साथ विशेष कोर्ट में उपस्थित हुए।

उन्होंने मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार को पुलिस रिमांड पर देने का अनुरोध किया। सीबीआई ने दोनों को नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने कार्यालय बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने उनके पास से मिले दो मोबाइल फोन को भी जब्त किए हैं।

थाने की गश्ती जीप ही रात में चुरा ले गया कोई सिरफिरा

दरभंगा (संवाददाता)। बिहार के दरभंगा जिले से चौंकाने वाला सामने आया है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल, कोई सिरफिरा रात को पुलिस की गश्ती जीप ही चुरा ले गया। इसके बाद उसने गाड़ी गड्ढे में लुढ़का दी और फिर भाग गया। सुबह लोगों ने जब पुलिस की गाड़ी लावारिस हालत में देखी तो तरह-तरह की चर्चा करने लगे। लोगों का कहना है कि कोई असामाजिक तत्व शराब के नशे में पुलिस की गाड़ी लेकर भाग रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर गाड़ी खेत में चली गई। यह मामला दरभंगा जिले के बिरौल का है। यहां हाई स्कूल के पास गुरुवार सुबह पुलिस का गश्ती वाहन खेत में लावारिस हालत में पड़ा मिला। इसकी खबर आग की तरह फैल गई और लोगों की भीड़ खेत में जमा हो गई। सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर अपने गार्यालय परिसर में गाड़ी को नहीं पाकर लावारिस हालत में पड़े वाहन के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने खेत से गाड़ी को बाहर निकाला और गैरेज पर ले जाया गया। ग्रामीणों में चर्चा है कि आखिर किस परिस्थिति में अंचल पुलिस निरीक्षक कार्यालय से पुलिस वाहन आधा किलोमीटर दूर सड़क से 10 फीट नीचे खेत के गड्ढे में लावारिस हालत में पाया गया। कई लोगों ने बताया कि जहां पुलिस कार्यालय ही सुरक्षित नहीं है, वहां पुलिस जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी।

अश्विनी चौबे के बयान से जेडीयू में खलबली, डैमेज कंट्रोल करने नीतीश के पास पहुंचे सम्राट चौधरी

पटना (संवाददाता)। केंद्र में एनडीए की नई सरकार के गठन के एक महीने के भीतर ही बिहार में सियासी पारा गर्माया हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का संदेश पार्टी को दे दिया। उनके बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में खलबली मच गई। जेडीयू ने तुरंत कह दिया कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार हैं। मामला ज्यादा गर्माता उससे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी डैमेज कंट्रोल करने सीएम आवास पहुंच गए। उन्होंने सीएम नीतीश से मुलाकात की और स्पष्ट किया कि बीजेपी को उनके नेतृत्व पर भरोसा है।

जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी ने गुरुवार देर शाम पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम नीतीश से मुलाकात की। इस मामले के जानकार बीजेपी नेताओं ने बताया कि नीतीश और सम्राट ने सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सम्राट ने मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता दिखाई। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी भी यह बात कह चुके हैं, तो इस पर कोई संशय नहीं है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में जेडीयू के सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन के लिए बीजेपी और जेडीयू एक साथ काम करती रहेगी। पीएम ने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास के राह पर चल रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ महीने पहले ही नीतीश कुमार ने आरजेडी-कांग्रेस का महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी।

दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुवार को कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए। सीएम का चेहरा कौन होगा इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। चौबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी इशारों में तंज कसते हुए उन्हें बाहरी बता दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर आयातित माल नहीं होना चाहिए। बता दें कि सम्राट चौधरी पहले लालू यादव की आरजेडी में रह चुके हैं।

अश्विनी चौबे के इस बयान से बिहार का सियासी पारा गर्मा गया। हालांकि, बीजेपी के नेताओं ने इससे किनारा कर दिया और इसे उनका निजी बयान भी करार दे दिया। इस बीच चुनावी रणनीतिकार रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी नीतीश कुमार को चाहकर भी नहीं हटा सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, ऐसे में 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू अहम भूमिका में आ गई। मोदी कैबिनेट में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मंत्री भी बने। अश्विनी चौबे के बयान के बाद जेडीयू उनपर तल्ख हो गई। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक कुमार झा ने कहा कि अश्विनी चौबे बीजेपी के अध्यक्ष नहीं हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और, वे स्पष्ट कर चुके हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। चौबे के बयान पर टिप्पणी करते हुए जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झाय ने भी कहा कि बिहार में नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है।

जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार?

केसी त्यागी बोले- राष्ट्रीय परिषद बैठक नहीं है

पटना (संवाददाता)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष पद नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले संगठन में बदलाव की चर्चा है लेकिन अध्यक्ष पद पर कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने नीतीश के अध्यक्ष पद छोड़ने की अटकलों पर सीधे सवाल के जवाब में कहा है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होता है जो नहीं बुलाई गई है। याद दिला दें कि दिसंबर में जब ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ा था तब एक ही दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर परिषद की बैठक थी। कार्यकारिणी में ललन के इस्तीफे के ऐलान के साथ नीतीश का नाम प्रस्तावित और पास हुआ जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय परिषद से हुआ।

जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की खबर जब से आई है तब से तमाम पदों को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है। सबसे ज्यादा अटकल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को लेकर है जिन्हें कभी अध्यक्ष तो कभी कार्यकारी अध्यक्ष और कभी संगठन महासचिव जैसे पदों का दावेदार बताया जा रहा है। नीतीश के गृह जिला नालंदा के रहने वाले मनीष वर्मा कुर्मी जाति से हैं। नीतीश ने अपनी जगह नालंदा के ही कुर्मी और आईएएस अधिकारी रहे आरसीपी सिंह को अध्यक्ष का पद दिया था लेकिन वो भरोसेमंद सलाहकार से मंत्री बनकर बागी हो गए। नीतीश खुद पार्टी अध्यक्ष पद पर रहते हुए एक सजातीय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, इसकी राजनीतिक संभावना कम है। राज्यसभा सांसद संजय झा को लेकर गंभीर चर्चा है कि नीतीश उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और नीतीश की एनडीए में वापसी के सूत्रधार भी।

रामभक्तों की सेवा से छत्तीसगढ़ हुआ धन्य : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने श्री रामलला दर्शन अभियान समितियों को किया सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे छत्तीसगढ़ के सभी रामसेवकों का अपने निवास परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्री साय ने सभी रामभक्त 6 समितियों को शाल श्रीफल और श्री रामलला की धातु की मूर्ति भेंटकर उनको सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सेवा कर लौटे प्रभु श्री रामलला दर्शन अभियान समिति के अंतर्गत सभी 6 समितियों के साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी समितियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजित होने के साथ ही रामभक्तों की 500 सालों की मनोकामना पूर्ण हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रभु श्रीराम का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ है और हम भांचा के रूप में श्री राम को पूजते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के इन 6 समितियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि ये समितियां स्वमेव प्रेरित होकर अयोध्या पहुंची और पूरी सेवाभाव के साथ वहां दर्शन करने आ रहे लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं को पूरे 60 दिनों तक भोजन कराया। यह छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ से अयोध्या में रामभक्तों के लिए चावल, सब्जी और डॉक्टर की टीम भेजी गई थी मैं उन टीमों को भी सराहना करता हूं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुगण अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन के बाद वाराणसी और प्रयागराज का दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ से अब तक 8 आस्था स्पेशल ट्रेनें रवाना हो चुकी है और 11 हजार रामभक्तों ने प्रभु श्री रामलला का दर्शन लाभ लिया है। इस अवसर पर विधायक और अयोध्या दर्शन समिति के संयोजक धरम लाल कौशिक ने सभी समितियों की सेवाभाव की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात है कि सभी 6 समितियों ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ रामभक्तों की सेवा की है। इस दौरान अयोध्या दर्शन समिति के सदस्यगण विधायक संपत लाल अग्रवाल और विरेंद्र श्रीवास्तव के साथ ही श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, रामलखन पैंकरा एवं ललित माखीजा मौजूद थे।

किसी को व्हीलचेयर, किसी को मोटराइज्ड ट्रायसायकल तो किसी को मिला कृत्रिम पैर

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से नि:शक्तजनों ने भी मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराते हुए अपने लिए सहायक उपकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी समस्याओं को सुना बल्कि संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांगजन को मौके पर ही व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्रायसायकल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित सायकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया।

जनदर्शन कार्यक्रम में तहसील लोरमी, जिला मुंगेली निवासी दिव्यांग अजय सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरा एक पैर कट जाने के कारण कृत्रिम पैर लगाया गया था, जो अब खराब हो गया है। मुझे एक नया कृत्रिम पैर की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया गया, उनके निर्देश पर दिव्यांग अजय सिंह राजपूत के पैर का माप लिया गया। कृत्रिम पैर बनने के बाद उन्हें कृत्रिम पैर प्रदान किया जाएगा।

जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर शैलेन्द्र नगर निवासी कु. केसर चंदवानी के अभिभावक ने बताया कि मेरी पुत्री कु. केसर चंदवानी जिसकी उम्र 11 वर्ष है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरी पुत्री के ईलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही नि:शक्त पुत्री के लिए व्हीलचेयर भी प्रदाय किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को सुनते हुए कु. केसर चंदवानी के लिए तत्काल व्हीलचेयर प्रदान किया। बाद में उन्हें मोटिफाइड व्हीलचेयर प्रदान किया जाएगा। जनदर्शन कार्यक्रम में बेमेतरा जिले से पहुंचे रोहित मारकंडे, आरंग के ग्राम जावा से आए बलराम वर्मा को मोटराइज्ड ट्रायसायकल और साजा निवासी बलराम को बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान किया गया। रामसागर पारा निवासी 67 वर्षीय देवानंद साहू को श्रवण यंत्र की जरूरत थी, उनकी समस्या सुनकर तुरंत जांच करवाकर मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने हाथों से विश्वनाथ कुमार एवं दो अन्य दिव्यांग को भी श्रवण यंत्र प्रदान किए।

कलेक्टर ने लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा

महासमुंद।

कलेक्टर प्रभात मलिक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैदानी स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विकासखंड पिथौरा अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र सोनासिल्ली, दुरुगपाली एवं मेमरा का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम के निर्धारित सभी आठ सेवा प्रावधानों के मानकों के अनुसार निरीक्षण किया। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम के 8 विषय सेवा प्रावधान, रोगियों के अधिकार, इनपुट, सहयोगी सेवाएं, क्लीनिक सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली परिणाम में बांटकर निर्धारित बिंदुओ पर विस्तृत रूप से निरीक्षण किया गया।

उन्होंने इन केन्द्रों में मरीजों का आवश्यकतानुसार त्वरित उपचार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दवाइयों की उपलब्धता तथा मौके पर मौजूद लोगों से भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक समय पर आएं और मरीजों का बेहतर उपचार करें। बीमारी के गंभीरता को देखते हुए ही जिला अस्पताल रेफर करें। जिले में चल रहे सिकलसेल जांच अभियान की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सिकल सेल से संबंधित जो भी मरीज आए उनका उचित परीक्षण एवं उपचार करें। आवश्यक जांच करते हुए पात्र पाए जाने पर दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सिकल सेल को मिटाने जनभागीदारी भी सुनिश्चित करें। अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले इसके लिए आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति लाएं तथा छूटे हुए लोगों का सर्वे कर उनका आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने यहां मोतियाबिंद के मरीजों की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर संधारित होने वाले आवश्यक रजिस्टर एवं रिकॉर्ड का जायजा लिया। कलेक्टर श्री मलिक ने उप स्वास्थ्य केंद्र दुरुगपाली में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मरीजों को त्वरित और बेहतर उपचार मिले। कलेक्टर ने विकासखंड अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट भी भेजना सुनिश्चित करें। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरिशंकर पैकरा, डीपीएम नीलू धृतलहरे एवं चिकित्सक मौजूद थे।

हथकरघा से जुड़कर आत्मनिर्भर बनेगी दीदियां

दंतेवाड़ा। जिला प्रशासन के द्वारा स्व सहायता समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उन्हे स्वरोजगार के ऐसे-ऐसे क्षेत्र उपलब्ध कराये जा रहे जिसको पहले सोचा नहीं गया था। जिला प्रशासन से जुड़कर से इन दीदियों ने आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अपने ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। इस क्रम में जिले में हथकरघा बुनकर इकाई की स्थापना की जा रही है, जिसमें गाँव के महिला स्व सहायता समूह तथा गाँव के युवा बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिल रहा है। इसके तहत दंतेवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत बालपेट के भैरमबंद, धुरली गाँव के समूह की 21 दीदियाँ तथा इच्छुक युवा वर्गों को चार माह का बुनकर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान सभी हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को 3 तीन हजार रूपये भी दिया जायेगा। इसके अलावा प्रशिक्षण के उपरांत इन सभी को 10 से 15 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाने का मौका भी मिलेगा।

इस प्रकार अब ग्रामीण महिलाएं किसी से कम नहीं है। अब वे हर क्षेत्र में अपने आपको साबित कर रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है।

सुशासन, पारदर्शिता और कामकाज की गति तेज करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और पहल

वर्षों बाद आज आम लोगों के लिए फिर खुले मुख्यमंत्री के दरवाजे, साय ने हफ्ते का एक दिन कर दिया नागरिकों के नाम

रायपुर। वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री-निवास के दरवाजे आज आम-नागरिकों के लिए पूरी तरह खुल गए। आज की ही तरह अब हर सप्ताह, गुरुवार के रोज, ये दरवाजे इसी तरह खुला करेंगे। इन खास दिनों में आम-औ-खास, कोई भी नागरिक, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर सकेगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री की ही इच्छा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन ने आज से एक खास कार्यक्रम-जनदर्शन - का दोबारा आगाज कर दिया है। आम नागरिकों से सीधी मुलाकात और सीधे संवाद के इस कार्यक्रम का फार्मेट ऐसा है कि मुख्यमंत्री निवास में सहज वातावरण में लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। वे अपनी शिकायतें, समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव आसानी से मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। एक साधारण सी टेबल के एक ओर मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है और दूसरी ओर फरियादी। आस-पास ही मुख्यमंत्री के सचिवालय के अधिकारियों सहित राज्य के वरिष्ठतम अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन के लिए मुस्तैद खड़े होते हैं। शिकायतों और सुझावों को बकायदा रजिस्टर्ड किया जाता है, नागरिकों को टोकन दिया जाता है, ताकि शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग की जा सके और आवेदक भी समय-समय पर प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए बकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें टोकन नंबर दर्ज करते ही प्रगति की जानकारी आवेदक के सामने होती है।

जनदर्शन के पहले दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इनमें महिलाओं भी खासी संख्या में शामिल थीं। कार्यक्रम को लेकर जितना उत्साह नागरिकों में था, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी उतनी ही उत्सुकता और आत्मीयता के साथ उनसे मुलाकात करते नजर आए। आवेदकों से आवेदन लेने के साथ-साथ वे उनसे पारिवारिक ढंग से बातें भी करते नजर आए। महिलाओं ने जब महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा तो श्री साय ने भी मुस्कुराते हुए विनम्रता से तुरंत आभार व्यक्त किया।

आवेदकों के साथ आए बच्चों के साथ उन्होंने अभिभावक की तरह घुल-मिल कर बातें की। कार्यक्रम में सहायता की आस लेकर कई दिव्यांग भी पहुंचे थे, इन सभी दिव्यांगों की उम्मीदें पूरी हुईं, मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें तत्काल ट्रायसायकल और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एक महिला ने अपने कैंसर पीड़ित पति के इलाज के लिए सहायता मांगी, तो मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें हर जरूरी सहायता दी जाएगी। वर्ष 2018 से पहले तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में यह कार्यक्रम इसी नाम से संचालित था। मुख्यमंत्री की इच्छा थी इसे दोबारा शुरू किया जाए, ताकि उनसे मिलने के इच्छुक ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को राज्य में सुशासन स्थापित करने और कामकाज में पारदर्शिता तथा तेजी लाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। आज कार्यक्रम के पहले दिन लोगों से बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान समय-सीमा में हो सके।

ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन

सूरजपुर। ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, राजेश अग्रवाल, अजय अग्रवाल, बिहारी कुलदीप, लवकेश पैकरा, बिज्जु दासन एवं राजेश्वर तिवारी, संभागायुक्त गोविंद राम चुरेंद्र, कलेक्टर रोहित व्यास, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, जिला शिक्षा अधिकारी रामललित पटेल, जिला मिशन समन्वयक शशिकांत सिंह, सहायक संचालक शिक्षा रविन्द्र देव सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत तिलक लगाकर और मिष्ठान खिलाकर किया गया। तत्पश्चात् सूरजपुर जिले अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास के बिंदुओं से की गई। जिसका प्रदर्शन प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार व गतिविधियों की संक्षिप्त झलकियों का प्रदर्शन किया गया। कस्तूरबा गांधी की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों के साथ-साथ उनके पालकों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट प्रदान करने की बात कही। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी, पालक व शिक्षकों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संदेश से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा सबसे अहम है। यदि स्कूली शिक्षक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए और संकल्प लेते हुए बच्चों को मन से पढ़ायेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे जिले के नाम को गौरवांवित करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा भी उपस्थित थे, उन्होंने विद्यार्थियों व अन्य उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी अपने में आत्मसात करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्या एक ऐसी चीज है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सभी शिक्षा अर्जित करते रहें और आगे बढ़ते रहें।

जिले में अब तक 142.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

सुकमा।

भू-अभिलेख कार्यालय जिला सुकमा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से शुरू की गई वर्षा मापन में अब तक सुकमा तहसील में 326.5 मिलीमीटर, छिन्दगढ़ तहसील में 145.4 मिलीमीटर, कोण्टा तहसील में 132.0 मिलीमीटर, गादीरास तहसील में 90.5 मिलीमीटर, तोंगपाल तहसील में 60.6 मिलीमीटर, दोरनापाल तहसील में 137.4 मिलीमीटर और जगरगुण्डा तहसील में 104.5 वर्षा दर्ज हुई है। इस प्रकार सुकमा जिले में 27 जून तक 142.4 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। इस मानसून सत्र जिले में 1734.5 मिलीमीटर औसत वर्षा संभावित है। वर्षा प्रतिवेदन 26 जून के आधार पर सर्वाधिक वर्षा छिंदगढ़ तहसील में 50.1 मिलीमीटर, सुकमा तहसील में 32.0 मिलीमीटर, गादीरास तहसील में 15.2 मिलीमीटर, कोण्टा तहसील में 15.0 मिलीमीटर, तोंगपाल तहसील में 11.6 मिलीमीटर, जगरगुण्डा तहसील में 10.2 मिलीमीटर और दोरनापाल तहसील में 7.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इस प्रकार 20.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है।

नवीन हक्कुम मेल बस को जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टर ने हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

सुकमा।

जिले में सीमा पर बसे आखिरी गांव के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय में आने एवं आस-पास के ग्रामीणों से संपर्क के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों के अभाव में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिसे देखते हुए ग्रामीणों को विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से और क्षेत्र में शांति स्थापना के साथ ही लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के प्रयासों के तहत जिले में सार्वजनिक बसों का संचालन प्रारंभ किया गया है। जिला प्रशासन एवं नीति आयोग के सहयोग द्वारा गांव-गांव तक बारहमासी आवागमन को सुगम बनाने के लिए यात्री बसों का परिचालन प्रारम्भ करने का निर्णय लेकर उक्त सुविधाओं को शुरू किया गया। इसी क्रम में आज नवीन हक्कुम मेल के संचालन हेतु जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टर श्री हरिस. एस ने हरी झण्डी दिखाकर नवीन बस को रवाना किया। इन बसों के सुचारू संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सुकमा ज़िला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी के माध्यम से संचालित बस रूट तैयार किए गए हैं, जिसमें ऐसे क्षेत्र जो अति संवेदनशील है उन्हें भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर इस अवसर पर श्री विश्वराज सिंह चौहान, पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित संयुक्त कलेक्टर श्री सूरज कश्यप, जिला परिवहन अधिकारी श्री शिवभगत रावटे, सीएमओ श्री एचआर गोंदे सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधी श्री विश्वराज सिंह चौहान ने कहा कि जिले के अति संवेदनशील ग्राम किस्टारम से जिला मुख्यालय सुकमा को सीधे जोड़ने से अब ग्रामीणों को हाट-बाजार, स्वास्थ्य सेवा लेने सहित अन्य कार्यों के लिए मुख्यालय तक आने के लिए अब दूसरों पर निर्भरता कम होगी।

कलेक्टर हरिस.एस कहा कि नवीन हक्कुम मेल बस प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील इलाकों के ग्रामीणों को बारहमासी सुगम आवाजाही की सुविधा हेतु बस का संचालन नियमित रुप से कराया जाएगा। बस सेवाओं से गांवों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ हमें बेहतर तरीके से सहायता भी प्राप्त होंगे जिससे हम मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने सहित नागरिक सेवाओं को और बेहतर कर सकेंगे। सौरभ कुमार पीपीआईए फेलो ने बताया कि जिले में नए रूट में बस संचालन से निश्चित ही आमजनों को सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन और नीति आयोग की पहल पर 03 हक्कुम मेल बस का संचालन क्रमशः जगरगुण्डा से कोंटा, तोंगपाल से सुकमा और भूसारास से ओलेर तक सफलतापूर्वक संचालन फरवरी माह से किया जा रहा है। जिससे संवेदनशील एवं दूरस्थ ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है।

बस का रूट चार्ट- हक्कुम मेल बस का संचालन सुबह 7 बजे से किस्टारम से प्रस्थान कर कासाराम, पोटकपल्ली, डब्बामरका, स्लातोंग, एलमागुण्डा, मिनपा चिन्तलनार, बुरापाल, चिन्तागुफा, पोलमपल्ली, दोरनापाल, केरलापाल होते हुए साढ़े 11 बजे तक सुकमा पहुंचेगी एवं उसी रूट से वापसी दोपहर सवा 2 बजे सुकमा से प्रस्थान कर शाम साढ़े 6 बजे तक किस्टारम पहुंचेगी।

कश्मीर घाटी में वोटिंग के रिकॉर्ड टूटे, लोगों को सरकार की गारंटी पर विश्वास : राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली (एजेंसी)।

संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति ने सभी निर्वाचित सांसदों को बधाई के साथ की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 4 दशकों में हमने कश्मीर में बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर भी देखा था। भारत के दुश्मन वैश्विक मंच पर इसको जम्मू कश्मीर की राय के तौर पर दुष्प्रचारित करते रहे हैं। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी में लोगों ने इसका करारा जवाब दिया है।उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। भारत के लोगों को यह पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी में विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास।

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, यह उस पर मुहर है। राष्ट्रपति ने कहा कि 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। यह लोकसभा अमृत काल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष की भी साक्षी बनेगी।

आगामी सत्र में मेरी सरकार इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। रिफंड की गति अब और तेज की जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। राज्यों के विकास से देश का विकास हम इसी भावना से आगे बढ़ते रहेंगे।

राष्ट्रपति ने बताया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने औसतन 8 प्रतिशत की रफ्तार से विकास किया है। वैश्विक महामारी का सामना करने के बावजूद भारत ने यह विकास दर हासिल की है। आज भारत अकेले ही विश्व के ग्रोथ में 15 फीसदी का योगदान दे रहा है। मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का काम करेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। चाहे सेमीकंडक्टर हो, सोलर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरी हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, या फाइटर जेट हो, भारत इन सब सेक्टर में अपना विस्तार कर रहा है। राष्ट्रपति ने बताया कि लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटी है। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वैलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर दिया गया है। गांव में डेयरी और फिशरी संबंधित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार छोटे किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण व्यवस्था पर काम कर रही है।

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत में ही किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज का भारत कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। निर्यात बढ़ाने को लेकर नीतियां बनाई गई हैं। दलहन और तिलहन का उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम किसानों की मदद कर रहे हैं। विश्व में ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड पूरी करने के लिए भारतीय किसानों के पास पूरी क्षमता है।

संसद परिसर में आप सांसदों ने लगाए 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन सांसदों का कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ हाथों में तख्ती लिए इन सांसदों ने 'तानाशाही नहीं चलेगी', 'केजरीवाल को रिहा करो' के नारे लगाए।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि वे सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर राज्यसभा में भी प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार करेंगे। आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) का समर्थन भी मिला है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, ये आपातकाल से भी अधिक तानाशाही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में सवाल पूछे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी इसे तानाशाही और इमरजेंसी करार दिया है। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि यह कानून नहीं है, इमरजेंसी है और तानाशाही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया।

कानून का राज सुशासन की पहली शर्त : सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। इसके लिए सुरक्षा व संरक्षा का बेहतर वातावरण होना चाहिए। सुरक्षा का वातावरण राज्य का दायित्व है। हमारी पुलिस इसका बखूबी निर्वहन करती है। समय के अनुरूप पुलिस का आधुनिकीकरण कर सकें, यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर यूपी-112 द्वितीय चरण के तहत उच्चीकृत पीआरवी को फ्लैग ऑफ किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डीजी कॉफ्रेंस में देश भर के पुलिस महानिदेशकों के सामने कानून के परिवर्तन के साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग की नई अवधारणा पर आधारित नई दृष्टि दी थी। उन्होंने स्ट्रिक्ट एंड सेंसेटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पांसिव, टेक्नोसेवी व ट्रेंड होने की बात कही थी। यूपी पुलिस ने इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है।

सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की सात वर्ष की प्रक्रिया को नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का अभियान है। पिछले सात वर्ष के अंदर यूपी पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी नई पहचान बनाई है, बल्कि यूपी को भी नई पहचान दिलाने में महती भूमिका का निर्वहन किया है। सात वर्ष में यूपी में कानून का राज दिखाई दिया है। कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान और विश्वास का प्रतीक बनाया तो राज्य में निवेश, व्यापार की नई संभावनाओं के साथ विकास और रोजगार के नए युग में ले जाने का कार्य किया।

सीएम योगी ने कहा कि निवेश, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसी होनी चाहिए, यूपी ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह केवल नारे नहीं, जमीनी हकीकत है। हमने बिना भेदभाव पारदर्शी प्रक्रिया से पुलिस बल में पुलिस भर्ती की तो समुचित प्रशिक्षण भी कराया। उन्होंने कहा कि पहली बार यूपी पुलिस बल के लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन किया गया। गत वर्ष पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। हमने यूपी-112 के रिस्पांस टाइम को कम करने और पीआरवी-112 की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। सात वर्ष में फोर व्हीलर के साथ टू व्हीलर भी शामिल किया गया, जिससे गली-मोहल्लों तक पीआरवी आमजन की सेवा के लिए पहुंच सके। इसके फ्लीट में 6278 फोर और टू व्हीलर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि कानपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कर्मचारी कल्याण के लिए एसी हेलमेट प्रदान करने की अभिनव पहल की गई। इसका निर्माण हैदराबाद की कंपनी ने किया है। कानपुर मेट्रो में काम कर रही एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने कानपुर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए सीएसआर गतिविधि के माध्यम से सहयोग दिया है। सीएम ने कानपुर ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी सुगौरव तिवारी को हेलमेट पहनाया।

झारखंड के पलामू में कन्स्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का हमला, तीन गाड़ियां फूंकी

पलामू (एजेंसी) । झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर थाना क्षेत्र में सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने एक रोड कन्स्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलकर तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वारदात बुधवार-गुरुवार देर रात की है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण करा रही कन्स्ट्रक्शन कंपनी से लेवी (रंगदारी) की मांग की थी। माना जा रहा है कि मुंह मांगी रकम न मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने वारदात की पुष्टि की है। नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने अभियान शुरू किया है।

बताया गया है कि हैदरनगर में डंडिला से सड़ेया गांव तक सड़क निर्माण चल रहा है। सीपीआई माओवादियों का एक हथियारबंद दस्ता डंडिला पहुंचा और एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टरों में आग लगा दी। इस सड़क का निर्माण अभय कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी कर रही है, जिसके मालिक हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह हैं। पुलिस सूत्रों ने वारदात के पीछे 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के दस्ते का हाथ बताया है। बीते छह महीने में झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, सिमडेगा और हजारीबाग जिले में अलग-अलग कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर नक्सलियों ने एक दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले किया है। 28 मई को रांची जिले के खलारी के पास नक्सलियों के एक दस्ते ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही कंपनी के साइट पर हमला बोलकर एक ट्रेलर में आग लगा दी थी, जिससे उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

पाली में रेल्वे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एवं एएसआई 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पाली (एजेंसी) । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर पाली-द्वितीयइकाई रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), पोस्ट फालना के इंस्पेक्टर कृपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर सुश्री डिम्पल व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) रमेश कुमार को 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की पाली-द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी। इसमें बताया कि आरपीएफ थाना फालना में दर्ज ऑनलाईन टिकिट मामले में उसकी दुकान से लाए गए लैपटॉप एवं अन्य दस्तावेज वापस करने एवं जाँच में मदद करने की एवज में आरोपियों द्वारा 2 लाख रुपए रिश्वत की राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस हरेन्द्र महावर के सुपरविजन मेंएसीबी पाली-द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्ष खींव सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान भी आरोपी रमेश कुमार द्वारा परिवादी से 35 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूले थे। एसीबी जयपुर की उप महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

राजस्थान में 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधी हस्तांतरित

झुंझुनूं (एजेंसी)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभ्य एवं विकसित समाज सभी वर्गों के विकास के लिए संवेदनशील रहता है। सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन जरूरतमंद को आर्थिक संबल देता है साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़े रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन, एकल नारी, दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है तथा इनके सामाजिक सुरक्षा के आवरण को कमजोर नहीं होने देगी।

श्री शर्मा झुंझुनूं में राज्यस्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि की राशि हस्तांतरण के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश के 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1 हजार 37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए

अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिये जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

2 लाख 41 हजार से अधिक नए लाभार्थी पेंशन योजनाओं से जुड़े : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि को 1 हजार रूपए से बढ़ाकर 1150 रूपए की है और इसमें चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जाएगी। संकल्प पत्र के हर एक वादे को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 88 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गठन के 6 माह के अल्प समय में 2 लाख 41 हजार से अधिक नए लाभार्थियों को इन पेंशन योजनाओं से जोड़ा है। साथ ही, झुंझुनूं जिले में 2 लाख 74 हजार से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32 करोड़ 27 लाख रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन पेंशन योजनाओं में डिजीटलकृत प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिससे आज पेंशनर्स को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है।

शिक्षा के बेहतर अवसर दे रही राज्य सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना के तहत 6 साल तक के बच्चों के लिए 1,500 रुपये तक प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 2,500 रुपये तक प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रेल तथा मई माह में 234 करोड़ रुपए व्यय कर 5 लाख 82 हजार बच्चों को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों को छात्रवृति के माध्यम से शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में मई तक 17 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय कर 16 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बाबा साहब के समता मूलक समाज की स्थापना के सिद्धांत पर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार अनाथ व असहाय बच्चों के लालन-पालन से लेकर बुजुर्गों के आर्थिक संरक्षण तक तथा बच्चों की पढ़ाई से लेकर युवाओं की नौकरी तक उन्हें आर्थिक सम्बल प्रदान कर सशक्त बना रही है।

घण्णा हेत सूं.., घण्णा कोर सूं.., घण्णा मान सूं... आभार।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद भी किया। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को योजना के तहत राशि बढ़ाए जाने पर बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया। बीकानेर से मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना की लाभार्थी कौशल्या ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि पेंशन में की गई राशि बढ़ोतरी से हमें आर्थिक संबल मिला है। ब्यावर से मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी रामरत्न ने कहा कि 'पेंशन री राशि बढ़ावा वास्ते घण्णा हेत सूं.., घण्णा कोर सूं.., घण्णा मान सूं... आपरो आभार। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने खेल मैदान में अशोक के पौधे का रोपण भी किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका सहित पूर्व विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों से स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े।

प्रधानमंत्री की गारंटी और प्रदेश सरकार का संकल्प हुआ पूरा

शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद कुछ राजनीतिक दलों द्वारा झूठे वादे किए गए तथा तुष्टिकरण की राजनीति एवं भ्रष्टाचार कर आमजन को गुमराह किया गया है लेकिन पिछले 10 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में देश में गरीब कल्याण, सीमा सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तीकरण के विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिससे विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। राज्य सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने, गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपये का बोनस देकर इसे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल करने, 450 रुपए में गैस सिलेण्डर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे हर वर्ग को राहत मिली है। साथ ही, प्रधानमंत्री की गारंटी तथा प्रदेश सरकार का संकल्प पूरा हुआ है।

खबरें देश-विदेश की

सांसद संजय सिंह का निलंबन हुआ खत्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता व सांसद संजय सिंह का राज्यसभा का निलंबन खत्म हो गया है। इस पर उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया है। आप नेता ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि संजय सिंह को पिछले साल मानसून सत्र के दौरान अमर्यादित व्यवहार की वजह से राज्यसभा से निलंबित किया गया था। उन्होंने लिखा, लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई। निलंबन खत्म हुआ। माननीय सभापति उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ जी। प्रिविलेज कमेटी के सभापति व सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार।

देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री दिल्ली एम्स में भर्ती

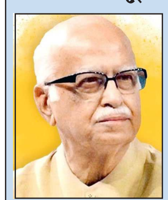

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देर रात को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद एम्स ले जाया गया है। हालांकि, कुछ सूत्रों का कहना है कि यह रूटीन चेकअप है। फिलहाल उन्हें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है।

31 मार्च को लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 फरवरी को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। इससे पहले 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

रांची (एजेंसी)। रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यानी 11 जुलाई तक वे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहेंगे।गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उनकी उनकी पेशी हुई और इसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई।

जमीन घोटाले के इसी मामले में जेल में बंद राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मो. सद्दाम, झामुमो नेता अंतु तिर्की, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष, संजीत कुमार एवं अन्य आरोपियों की भी गुरुवार को अदालत में ऑनलाइन पेशी हुई और उनकी हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं। इस मामले में अब तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बड़ा रेल हादसा: पैसेंजर ट्रेन के नौ डिब्बे पटरी से उतरे, 70 लोग घायल

मॉस्को (एजेंसी)। रूस के उत्तर-पश्चिमी कोमी क्षेत्र में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में कम से कम 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन के नौ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 70 यात्री घायल हुए हैं। फिलहाल, हादसे में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है।

आपातकालीन सेवाएं और मेडिकल टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। भारी बारिश दुर्घटना का संभावित प्रमुख कारण हो सकती है। यात्री ट्रेन उत्तर पूर्वी कोमी में वोरकुटा से नोवोरोस्सिएस्क के ब्लैक सी बंदरगाह जा रही थी। ट्रेन में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, हादसा बुधवार को इंटा शहर के पास हुआ।

ब्रसेल्स में गोलीबारी में 2 की मौत, 3 घायल

ब्रसेल्स (एजेंसी)। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के सेंट-गिल्स में मिडी ट्रेन स्टेशन के पास हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को ये बात कही गई। गोलीबारी रात 1 से 2 बजे के बीच एक कैफे के पास की गई। घायलों में से एक को मामूली चोट आई है, जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हैं। इस गोलीबारी में शामिल लोग फिलहाल फरार हैं। ब्रसेल्स पुलिस ने तुरंत एक सुरक्षा घेरा बनाया और शूटरों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी। अपराधियों ने गोलीबारी क्यों की, उनका क्या मकसद था, उसके बारे में अभी पता नहीं चला है। अभी तक किसी भी संदिग्ध को पकड़ा नहीं गया है।

तख्तापलट की कोशिश नाकाम, टैंक लेकर राष्ट्रपति भवन में घुसा सेना का जनरल गिरफ्तार

ला पाज़ (एजेंसी)। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो गई है। बोलिवियाई सशस्त्र बलों के बख्तरबंद वाहन और सैनिकों ने ला पाज़ में राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई। बोलिवियाई पुलिस ने विद्रोही सैन्य कमांडर जनरल जुआन जोस जुनिगा को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने असफल तख्तापलट की कोशिश का नेतृत्व किया था। बोलिवियाई राष्ट्रपति लुइस आर्से ने तख्तापलट की कोशिश की निंदा की और नागरिकों से लोकतंत्र की रक्षा करने और संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने एक नए सेना कमांडर के नाम की घोषणा की, जिन्होंने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया। इससे पहले, सैनिकों ने जनरल जुनिगा के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन के बाहर एक चौक प्लाजा मुरिलो पर मार्च किया और पुराने सरकारी मुख्यालय, पलासियो क्वेमाडो में जबरन घुस गए। सशस्त्र सैनिकों की मौजूदगी के बाद नागरिकों ने सैन्य कदम की निंदा की।

पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में द. अफ्रीका : छह बार फाइनल से चूके, 32 साल तक चोकर्स कहे गए; अब बदली कहानी

त्रिनिदाद (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ नौ विकेट से पहला सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ टीम ने खुद पर लगे चोकर्स के दाग को मिटा दिया। यह पहला मौका है जब अफ्रीकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। 32 साल में पहली बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। इससे पहले सेमीफाइनल में टीम आठ (1992, 1999, 2007, 2009, 2014, 2015, 2023, 2024) बार पहुंची जहां उन्हें छह बार हार का सामना करना पड़ा। वहीं, 1999 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया एक मैच टाई हो गया था। हम यहां आपको दक्षिण अफ्रीका के टी20 विश्व कप में सफर के विषय में बता रहे हैं...

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 विश्व कप 2007 का सुपर-8 का आखिरी मुकाबला खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने उन्हें 37 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की नाबाद 50 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में पांच विकेट पर 153 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में नौ विकेट पर सिर्फ 119 रन ही बना सकी थी। इस मैच में आरपी सिंह ने चार विकेट हासिल कर विरोधियों की कमर तोड़ी थी। ग्रुप ई का हिस्सा रही दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 में कुल तीन मैच खेले थे। इनमें उन्हें दो में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा था जबकि ग्रुप स्टेज पर उन्होंने अपने दोनों मैच जीते थे।

ग्रुप स्टेज पर दो मैचों में एक मुकाबला जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका सुपर-8 में पहुंची थी। यहां उन्हें तीन मैचों में सिर्फ एक जीत मिली जबकि दो में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका को सुपर-8 के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने उमर अकमल की 51 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में सात विकेट पर 51 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में सात विकेट पर सिर्फ 137 रन ही बना सकी थी। उन्हें इस मैच में 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। टी20 विश्व कप 2014 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि, भारत ने उनकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। मीरपुर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 172 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने विराट कोहली की नाबाद 72 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 19.1 ओवर में चार विकेट पर 176 रन बनाए थे और छह विकेट से जीत दर्ज की थी। ग्रुप-1 में रही इस टीम ने चार में से तीन मैचों में जीत दर्ज की थी। सुपर 10 के ग्रुप-1 में रही दक्षिण अफ्रीका को चार में से दो मैचों में जीत मिली थी जबकि दो में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुपर-10 के आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को श्रीलंका के खिलाफ आठ विकेट से जीत मिली थी। इसके बावजूद नेट रनरेट की वजह से वह क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप 2021 में सुपर-12 का आखिरी मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। इसके बावजूद वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में दो विकेट पर 189 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 179 रन ही बना सकी थी। अफ्रीकी टीम को इस मुकाबले में 10 रनों से जीत मिली थी। पांच मैचों में चार जीत के बावजूद उनका नेट रनरेट +0.739 ही रहा था जिसकी वजह से वह ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। टी20 विश्व कप 2022 में दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप-2 में उनके आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड्स ने 13 रनों से हराया था। नीदरलैंड्स ने 20 ओवर में चार विकेट पर 158 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 145 रन बनाए थे। ग्रुप स्टेज पर उन्हें पांच मैचों में सिर्फ दो में ही जीत मिली थी। वहीं, तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया। इसमें दक्षिण अफ्रीका ने नौ विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 32 साल बाद फाइनल में एंट्री की। मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका दूसरी ऐसी टीम है जिसने अपने सभी मुकाबले अब तक जीते हैं। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.5 ओवर में 10 विकेट पर 56 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाए और मौजूदा टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई।

सेमीफाइनल के दबाव में बिखरा अफगानिस्तान, द. अफ्रीका की आसान जीत

त्रिनिदाद (एजेंसी)। टी20 विश्व कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच नौ विकेट से जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.5 ओवर में 10 विकेट पर 56 रन बनाए। इस स्कोर पर ऑलआउट होना टी20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच में किसी टीम का सबसे न्यूनतम स्कोर है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाए और मौजूदा टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मौजूदा टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीमें अब तक अजेय हैं। यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2014 में वह सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई थी। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ मैच जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया था।

57 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका फजलहक फारुकी ने पांच रन के स्कोर पर दिया। उन्होंने क्विंटन डिकॉक को बोल्ड किया। इसके बाद मोर्चा रीजा हेंड्रिक्स और एडेन मार्करम ने संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 55 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज हेंड्रिक्स ने 29 और कप्तान मार्करम ने 23 रन बनाए। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने महज 57 रनों का लक्ष्य रखा। इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और विरोधी गेंदबाजों के सामने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन 10 रन अजमतुल्लाह उमरजई ने बनाए। शेष कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से मार्को यानसेन और तबरेज शम्सी ने तीन-तीन विकेट चटकाए। वहीं, कागिसो रबाडा और एनरिक नॉर्त्जे ने दो-दो विकेट हासिल किए।

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में लगी 11,000 करोड़ रुपये की बोली, भारती एयरटेल सबसे आगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगी। इसमें भारती एयरटेल सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है। सरकार की ओर से किए जा रहे 96,000 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम की नीलामी में सबसे ज्यादा मांग 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की रही। टेलीकॉम एनालिस्ट पराग कर के मुताबिक 900 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए 6,985 करोड़ रुपये की बोली लगी है और वहीं 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए 3,579 करोड़ रुपये की बोली लगी है। पराग कर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 2,100 मेगाहर्ट्ज में भारती एयरटेल द्वारा 545 करोड़ रुपये की एकमात्र बोली लगाई गई है। वहीं, वोडाफोन आइडिया (वीआई) 2500 मेगाहर्ट्ज में बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी थी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा इस नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज, 2,300 मेगाहर्ट्ज, 2,500 मेगाहर्ट्ज, 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड नीलामी के लिए रखे गए थे।

इस नीलामी प्रक्रिया में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने भाग लिया। एनालिस्ट का कहना है कि स्पेक्ट्रम की ये नीलामी देश में 5जी कवरेज को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगी। इससे सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 5जी यूजर्स की संख्या 2029 के अंत तक 84 करोड़ के करीब पहुंच सकती है, जो कि कुल मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या का 65 प्रतिशत होगा। इससे पहले 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी।

भारत में 10 में से 8 एमएसएमई बना रहे 2025 में क्लाउड पर खर्च बढ़ाने की योजना

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में हर 10 में से 8 या 81 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां (एमएसएमई) 2025 में अपना क्लाउड पर खर्च में इजाफा कर सकती है। इसकी वजह एमएसएमई द्वारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम), फाइनेंसियल सर्विसेज और बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में निवेश करना है। गुरुवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि डिजिटलाइजेशन में एमएसएमई को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर की अधिक लागत, बजट की कमी, एकीकरण और स्किल की कमी शामिल है।

देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर एक बड़ी भूमिका निभाता है। आने वाले समय में इनकी संख्या 6.3 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। जोहो के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस प्रवल सिंह का कहना है कि इस एमएसएमई दिवस पर हम इन इकाइयों की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी मुश्किल कारोबार बड़ा करने के लिए सही सॉल्यूशन न होना है। रिपोर्ट में बताया गया कि 73 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयां आने वाले 6 महीने में अपने विकास को लेकर आशावादी हैं। एमएसएमई बड़े स्तर पर कारोबार में तीन चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिसमें आर्थिक अनिश्चितता (54 प्रतिशत), महंगाई (44 प्रतिशत) और स्किल लेबर की कमी (33 प्रतिशत) हैं।

एमएसएमई का फोकस डिजिटल अनुभव को मजबूत बनाने को लेकर है। अपनी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए वे आईटी और क्लाउड सॉल्यूशन पर निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि 97 प्रतिशत एमएसएमई का कहना है कि वे अपनी आय 20 प्रतिशत हिस्सा आईटी और क्लाउड सर्विसेज पर खर्च करेंगे।

एसएमई, एमएसएमई को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है फोनपे का भुगतान समाधान

नई दिल्ली (एजेंसी)।

विश्व एमएसएमई दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इस मौके पर फोनपे पेमेंट गेटवे (पीजी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को सहारा देने के लिए गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। फोनपे पेमेंट गेटवे ने शेयर किया कि वह पहले से ही टियर 2 शहरों और उससे आगे आधे से अधिक एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के साथ पीजी समाधान सक्षम करने के लिए काम कर रहा है। मुख्य फोकस रीजनल बिजनेस को सशक्त बनाने पर है। इससे समावेशी विकास को बल मिलेगा और व्यवसायों को तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी।

ज्यादातर पेमेंट गेटवे 2 प्रतिशत का लेनदेन शुल्क लेते हैं। वहीं फोनपे पीजी के पास नए व्यापारियों के लिए फ्री में शामिल होने के लिए एक विशेष प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में कोई छिपा हुआ शुल्क, सेटअप शुल्क या सालाना रखरखाव शुल्क नहीं है। इसके अलावा, फोनपे पीजी भरोसेमंद है। यह व्यापारियों के लिए 100 प्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित करता है। यह सक्रिय रूप से डाउनटाइम का पता लगाता है और रियल टाइम में लेनदेन को सुनिश्चित करता है।

फोनपे पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन मर्चेंट्स के प्रमुख अंकित गौर ने कहा, इस विश्व एमएसएमई दिवस पर, फोनपे पीजी पूरे भारत में एमएसएमई और एसएमई को सशक्त बनाने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है। हम टियर 2, टियर 3 शहरों और उससे आगे के व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। बिना बाधा के पेमेंट समाधान कर और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर हम उन्हें नए ग्राहकों और बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बना रहे हैं, जो पहले पहुंच से बाहर थे।

उन्होंने आगे कहा, हमारे पास ऑनबोर्डिंग के बाद से पहले तीन महीनों के लिए शून्य लेनदेन लागत की एक यूनिक पेशकश है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक एसएमई/एमएसएमई भुगतान गेटवे की ओर से दी जाने वाली सुविधा और सुरक्षा को अपना सकें और उसका उपयोग कर सकें। फोनपे पीजी के लिए प्रतिबद्धता पूरे देश में व्यवसायों के लिए विकास क्षमता को अनलॉक करना और अधिक जीवंत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। फोनपे पीजी को व्यापारी भी पसंद करते हैं। यह 100 प्रतिशत सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करता है। एमएसएमई पेमेंट लिंक समाधान का उपयोग कर आसानी से लिंक के माध्यम से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें ग्राहकों के साथ जनरेट और शेयर किया जा सकता है।

वे आसानी से पेमेंट प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एसएमएस, ईमेल या उनकी पसंद के किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट (भुगतान) लिंक भेज सकते हैं। एसएमई के लिए कनेक्ट सेशन फोनपे की ओर से एक मल्टी-सिटी पहल का हिस्सा है, जिसे उभरते शहरों में आयोजित करने की योजना है। वे एसएमई के वरिष्ठ नेतृत्व और प्रमुख निर्णयकर्ताओं को अपनी ऑनलाइन मौजदूगी को अनुकूलित करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तकनीकी इनोवेशन का लाभ उठाने के लिए एक प्लेटफार्म देते हैं।

फोनपे पीजी ने हाल ही में अपने रेफरल प्रोग्राम की शुरुआत की भी घोषणा की है। फोनपे पीजी पार्टनर प्रोग्राम उन सभी लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो किसी व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद करते हैं। एक रेफरल पार्टनर के रूप में, वे अपने ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेने और व्यवसाय के विकास में तेजी लाने के लिए अपने ग्राहकों को रेफर कर सकते हैं।

सपाट खुला शेयर बाजार, निफ्टी 23,800 के ऊपर

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई है। बाजार के ज्यादातर सूचकांक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। सुबह 9 .20 बजे तक सेंसेक्स 99 अंक फिसलकर 78,575 और निफ्टी 35 अंक गिरकर 23,834 पर था। बाजार का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। एनएसई पर 1,278 शेयर हरे निशान में, जबकि 792 शेयर लाल निशान में हैं। लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेजी है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 183 अंक या 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 55,429 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 35 अंक या 0.20 प्रतिशत की तेजी के 18,334 पर है।

सेक्टर के हिसाब से देखें तो फार्मा, रियल्टी और मेटल इंडेक्स में तेजी है। आईटी, फिन सर्विस, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक इंडेक्स पर दबाव बना हुआ है। सेंसेक्स पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स हैं।

एसबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10 हजार करोड़ जुटाए

मुंबई (एजेंसी)।

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 15 सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह राशि 7.36 प्रतिशत की कूपन रेट पर जुटाई है। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाली राशि का उपयोग राजमार्गों, पावर प्लांट, बुनियादी ढांचे और किफायती आवास क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

एसबीआई ने कहा कि इस निर्गम को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह पांच हजार करोड़ रुपये के आधार निर्गम आकार के मुकाबले लगभग चार गुना ज्यादा अभिदान मिला। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इस निर्गम से लॉन्ग टर्म बॉन्ड कर्व विकसित करने में मदद मिलेगी और अन्य बैंकों को भी लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत की डेटा सेंटर क्षमता में 5 गुना का हो सकता है इजाफा : रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। डिजिटाइजेशन से डेटा के बढ़ते उपयोग के कारण भारत के डेटा सेंटर की क्षमता में आने वाले साल में 5 गुना का इजाफा हो सकता है। गुरुवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि देश को नियोजित 2.32 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता के अलावा 1.7 से लेकर 3.6 गीगावाट के अतिरिक्त डेटा सेंटर की आवश्यकता है। कुशमैन और वेकफील्ड की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत 2028 तक प्रति वर्ष 464 मेगावाट की कोलोकेशन डेटा सेंटर क्षमता जोड़ेगा।

2023 की दूसरी छमाही तक देश के शीर्ष सात शहरों में कोलोकेशन डेटा सेंटर क्षमता 977 मेगावाट थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 258 मेगावाट की कोलोकेशन डेटा सेंटर क्षमता अकेले 2023 में ही बनाई गई। वहीं, 2022 में कुल 126 मेगावाट की डेटा सेंटर क्षमता जोड़ी गई थी। ऐसे में पिछले वर्ष के मुकाबले नई डेटा सेंटर बनाने की रफ्तार में 105 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। डेटा सेंटर क्षमता के तेजी से बढ़ने की वजह डेटा आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटलीकरण का तेजी से बढ़ना और बड़े स्तर पर डेटा की खपत को माना जा रहा है। भारत में डेटा की खपत में पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़त हुई है। एक आम भारतीय मोबाइल फोन औसत 19 जीबी से ज्यादा की डेटा खपत करता है। यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।

संपादकीय

पेपर लीक : भविष्य दांव पर

सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू कर दिया है। इस एंटी-पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक या उत्तर-पुस्तिका से छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल की सजा होगी जिसे दस लाख तक के जुर्माने के साथ बढ़ा कर पांच साल तक भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चार महीने पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे चुकी थीं। इस कानून का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए द्वारा आयोजित अन्य तमाम परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों पर अब न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून से पहले राज्यों में नकल रोकने और परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकने संबंधी कानून बनाए गए हैं।

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में ऐसे कानून हैं। हालांकि ये उस तरह के नतीजे देने में असफल रहे हैं, जिनके बलबूते परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जा सके।

इस नये कानून द्वारा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रमुख और सदस्यों को लोक सेवक माना जाएगा ताकि उनके खिलाफ अपराध के साथ ही भ्रष्टाचार का मामला भी चलाया जा सके। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर उठने वाली उंगलियों के कारण युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। बार-बार परीक्षा प्रणालियों पर संदेह और उनकी पारदर्शिता धूमिल पड़ने के चलते प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त होती जा रही है। चूंकि अब यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आ गया है, इसलिए कोई भी पुलिस अधिकारी बगैर वारंट भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। भले ही यह फैसला लेने में सरकार ने काफी ढिलाई बरती है लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद क्योंकि उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए परीक्षार्थियों का समूचा भविष्य ही दांव पर लगा होता है। परीक्षाओं में धांधली होनहार युवाओं को नैतिक तौर पर बुरी तरह तोड़ देती है।

हालांकि सख्त कानून बनाने में वक्त लगता है। विशेषज्ञों की राय और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसे उस सख्ती से लागू किया गया ताकि भविष्य में इस तरह का कोई संकट ही न खड़ा हो सके। साथ ही, इस तरह के अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। देखा जाना है कि कानून सख्त किए जाने के बाद पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधलियों पर नकेल कसने में हम किसने सफल होते हैं।

अब भारत को विभिन्न क्षेत्रों में अपने सूचकांक तैयार करना चाहिए

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल ही के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवत जान बूझकर गलत दर्शाया गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजेर देश को बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्रा स्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है, अर्थात इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाकर पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है।

इसी प्रकार, भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, इस भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव क्यों कराए गए हैं, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, आदि। परंतु, भारतीय मतदाताओं ने इन लोक सभा चुनावों में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। न ही, ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और न ही गर्मी का प्रभाव चुनावों पर पड़ा। हालांकि सत्ताधारी दल को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ कम स्थान जरूर प्राप्त हुए हैं परंतु देश में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सामान्यत: शांति के साथ सम्पन्न हो गए। साथ ही, विपक्षी दलों को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक स्थान मिले हैं और उन्होंने भी चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है। चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वें स्थान पर बताई गई है। जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है, परंतु पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को ही जैसे खतरे में बताया जा रहा है और एक तरह से

भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल पश्चिमी देशों में कुछ शक्तियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकतें विभिन्न सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़तीं हैं।

कुछ समय पूर्व एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में यह बताया गया था कि भारत की तुलना में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, एथीयोपिया, नेपाल, भूटान आदि देशों में भुखमरी की स्थिति बेहतर है। अर्थात, सर्वे में शामिल किए गए 121 देशों की सूची में श्रीलंका का स्थान 64वां, म्यांमार का 71वां, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां, एथीयोपिया का 104वां एवं भारत का 107वां स्थान बताया गया था। जबकि पूरा विश्व जानता है कि व श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है जिसके चलते इन देशों के नागरिकों के लिए दो जून की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि, भारत कई देशों को आज खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिर किस प्रकार उक्त सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि भारत की आर्थिक तरक्की को विश्व के कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारत के बारे में इस प्रकार के सूचकांक जारी कर भारत की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

युद्ध की विभीषिका झेल रहे एथीयोपिया में नागरिक अपनी भूख मिटाने के लिए घास जैसे भारी पदार्थों को खाकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जीवन यापन करने वाले नागरिकों को भुखमरी के मामले में भारत के नागरिकों से बेहतर स्थिति में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन लोगों को खाने पीने सम्बंधी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। फिर भी भारत के नागरिकों को भुखमरी सूचकांक में ईथीयोपिया के नागरिकों की तुलना में इतना नीचे बताया गया है। अब कौन इस प्रकार के सूचकांकों पर विश्वास करेगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांक को आंकने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से केवल 3000 नागरिकों को ही इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वे का सैम्पल बनाते समय भारत जैसे विशाल देश के लिए अपर्याप्त संख्या का उपयोग किया गया है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग पर कार्य कर रही संस्था स्टैंडर्ड एंड पूअर ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था का आंकलन करते हुए भारत के सम्बंध में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक किया है एवं कहा है कि वह भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के उद्देश्य से भारत के आर्थिक विकास सम्बंधी विभिन्न पैमानों का, आधारभूत ढांचे को विकसित करने एवं भारत के राजकोषीय घाटे को कम करने से सम्बंधित आंकड़ों एवं प्रयासों का गम्भीरता से लगातार अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहा है। आगे आने वाले दो वर्षों के दौरान यदि उक्त तीनों क्षेत्रों में लगातार सुधार दिखाई देता है तो भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- है, जो निवेश के लिए सबसे कम रेटिंग की श्रेणी में गिनी जाती है।

किसी भी देश की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को यदि अपग्रेड किया जाता है तो इससे उस देश में विदेशी निवेश बढ़ने लगते हैं क्योंकि निवेशकों का इन देशों में पूंजी निवेश तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। साथ ही, अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त देशों की कम्पनियों को अन्य देशों में पूंजी उगाहना न केवल आसान होता है बल्कि इस प्रकार लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की राशि भी कम देनी होती है। किसी भी देश की जितनी अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग होती है उस देश की कम्पनियों को कम से कम ब्याज दरों पर ऋण उगाहने में आसानी होती है। परंतु, भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए स्टैंडर्ड एंड पूअर को दो वर्षों का समय क्यों चाहिए? जब इन समस्त क्षेत्रों में लगातार सुधार होते साफ दिख रहा है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई विदेशी संस्थान (विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आदि) आगे आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर बहुत उत्साहित हैं एवं आर्थिक प्रगति के साथ साथ राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करते रहते हैं। फिर भी, स्टैंडर्ड एंड पूअर को भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के लिय दो वर्षों का अतिरिक्त समय चाहिए। वैश्विक पटल पर पश्चिमी देशों के विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के चलते, अब समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानों पर अपनी रेटिंग तय करने के लिए अपने सूचकांक विकसित करने पर विचार करे क्योंकि वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों द्वारा जितने भी सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं उसमें भारत के संदर्भ में वस्तुस्थिति का सही वर्णन नहीं किया जा रहा है।

समाज सेवा करते-करते राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाने वाले ओम बिरला का जीवन बड़ा प्रेरक है

ओम बिरला में ऐसा क्या है जो उन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंचाता है। अपने कोटा शहर में जरूरतमंद लोगों को कपड़े, दवाएं, भोजन पहुंचाते-पहुंचाते बिरला कब राष्ट्रीय राजनीति के सितारे बन गए, यह एक अद्भुत कहानी है। प्रधानमंत्री ने सदन में उनके द्वारा चलाए जा रहे अनेक सामाजिक कार्यों की चर्चा की। उनकी सरलता,सहजता और सदन चलाने की उनकी क्षमताएं प्रमाणित हैं। अब जब वे ध्वनिमत से लोकसभा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, तब उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। यह भी शुभ रहा कि कांग्रेस ने प्रारंभिक चर्चाओं के बाद भी मत विभाजन की मांग नहीं की और उनका चयन सर्वसम्मत से हुआ। इससे संसद की गरिमा बनी और परंपराओं का पालन हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले समय में लोकसभा ज्यादा बेहतर तरीके से अपने कामों को अंजाम दे सकेगी।

बलराम जाखड़ के बाद वे दूसरे ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने यह गरिमामय पद दुबारा संभाला है। इस बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि नए सांसदों को बिरला से सीखना चाहिए। मोदी ने कहा कि संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। सदन में आचरण और नियमों का पालन जरूरी है। सदन की गरिमा और परंपराओं का पालन अध्यक्ष की बहुत महती जिम्मेदारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बिरला जी का यह कार्यकाल उदाहरण बनेगा। जहां गंभीर बहसें होंगी और शासकीय काम के साथ विमर्शों का नया आकाश खुलेगा।

राजस्थान के कोटा जिले में 23 नवंबर,1962 को जन्में ओम बिरला का समूचा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन सेवा, समर्पण और उससे उपजी सफलताओं से बना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम प्रारंभ कर वे राजस्थान में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 2003, 2008 और 2013 में तीन बार राजस्थान विधानसभा में विधायक निर्वाचित किए गए। 2014 से वे लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। इस तरह वे एक सफल जनप्रतिनिधि के रूप में कोटा के लोगों का दिल जीतते रहे हैं। 17 वीं लोकसभा में अध्यक्ष चुने जाते ही वे राष्ट्रीय फलक पर छा गए। अपने तमाम फैसलों की तरह उस समय नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। किंतु अपनी सौजन्यता, कुशल सदन संचालन और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव न होने के बाद भी अकेले वरिष्ठ सांसदों के पैनल के आधार उन्होंने सदन चलाया । उनका सहज अंदाज और हल्की मुस्कान,मीठी डांट से सदन को चलाने का तरीका उन्हें इस बार इस पद का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बना चुका था। अब कोटा की स्थानीय राजनीति से राष्ट्रीय फलक पर आए बिरला सदन की उपलब्धि बन चुके हैं।

बिरला राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे। उनके मन में समाजसेवा की भावना इसी संगठन से उपजी और वे विविध प्रकल्पों के माध्यम से इसी काम में रम गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में 2012 में परिधान नाम कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके तहत समाज के कमजोर वर्गों को किताबें और कपड़े वितरित किए जाते थे।

इसके साथ ही रक्तदान और मुफ्त दवा वितरण के आयोजनों से वे लोगों के दिलों में उतरते चले गए। फिर उन्होंने मुफ्त भोजन कार्यक्रम भी चलाया। उनका संकल्प था उनके लोग भूखे न सोएं। इस तरह वे बहुत संवेदनशील और बड़े दिलवाले सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता की तरह सामने आते हैं। यह उन हाशिए के लोगों की दुआएं ही थीं कि बिरला आज सत्ता राजनीति के शिखर पर हैं।

भाजपा को एक दल के रूप में इस बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है और उसकी निर्भरता राजग के सहयोगियों पर बढ़ी है। इसी तरह सदन में प्रतिपक्ष ज्यादा ताकतवर हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी मौजूद होंगे। मोदी की तीसरी सरकार में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना भी एक बड़ी सूचना है। पिछले दो सदनों में कांग्रेस के इतने सदस्य नहीं थे कि वह नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सके। इससे नेता प्रतिपक्ष अब लोकलेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे और सरकारी खर्चों पर टिप्पणी कर सकेंगें। इस बदले हुए परिदृश्य में सदन में प्रतिपक्ष की आवाज भी प्रखर होगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए सत्ता पक्ष पर अंकुश और प्रतिपक्ष को संरक्षण देने की अपील की। उम्मीद की जानी कि ओम बिरला अपने बड़े दिल से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्रदान करेंगें। फिलहाल तो उन्हें शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं।

मोदी गठबंधन पूर्व गठबंधन सरकारों से अलग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है । भारत में गठबंधन सरकारों के काम करने और उसके संचालन का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। गठबंधन में सरकार का नेतृत्व करने वाले दल और नेता पर साथी दल अधिक से अधिक मंत्री बनाने और जिन्हें वो चाहते हैं उन्हें मंत्री के रूप में स्वीकार करने तथा बाद में अपने अनुसार नीतियां बनवाने या बदलवाने के लिए दबाव डालते रहें। अपनी बात न मानने पर समर्थन वापसी तथा सरकार के अस्थिर होने, गिर जाने, कमजोर हो जाने की घटनाएं भी हमने देखी हैं।

जानते और चाहते हुए भी कई बार प्रधानमंत्री को नीतियों के स्तर पर वैसे कदम उठाने से स्वयं को रोकना पड़ा या उठाए हुए कदम वापस लेने पड़े जो देश के लिए आवश्यक थे। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान गठबंधन सरकार को लेकर कोई आशंका उठती है तो उसे इस पृष्ठभूमि में तत्काल खारिज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि विपक्ष इसे कमजोर व लंगड़ी सरकार बता रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह टिप्पणी कर रहा है कि वे शेर से बकरी हो गए हैं तो उससे पूछा जाना चाहिए कि इसके समानांतर अगर सत्ता में वे आते तो उनकी सरकार कैसी होती? कम से कम इस सरकार में एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसके आसपास भी कोई दल नहीं। राहुल गांधी जी के शब्दों में अगर यह क्रिपल्ड सरकार है तो 'इंडिया' की सरकार क्या ठोस चट्टान वाली होती?

कहने का तात्पर्य कि हमें आशंकाओं या विपक्ष की अतिवादी आलोचनाओं में जाने की जगह वास्तविकताओं के आधार पर इसके वर्तमान एवं भविष्य का आकलन करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर तलाशना चाहिए कि आखिर अब मंत्रिमंडल गठन के बाद सरकार कैसे काम करेगी? सरकार की दिशा और दशा क्या होगी? यह बात सही है कि हमने पिछले 10 वर्षों में ऐसी मोदी सरकार देखी है जिसके पास अपनी भाजपा का बहुमत था और ऐसे बड़े फैसले हुए, कदम उठाए गए, संवैधानिक-प्रशासनिक एवं नीतियों के स्तर पर ऐसे आमूल बदलाव के निर्णय हुए जिनकी पहले कल्पना नहीं थी। स्वयं सरकार को और देश को 10 वर्षों के इस अभ्यास से बाहर निकालना कठिन होगा, लेकिन क्या वाकई इससे बाहर निकालने की अभी ही आवश्यकता महसूस होती है या संभावना दिखाई देती है?

ध्यान रखिए कि पूर्व की गठबंधन सरकारों की तरह इस सरकार के गठन, मंत्रियों को सरकार में लेने या विभागों के बंटवारे में किसी तरह का खींचतान हमारे सामने नहीं आया। यह अन्य गठबंधन सरकारों से इसे अलग करता है। 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में साथी दलों के 11 मंत्रियों का होना ऐसी संख्या नहीं है जिसे लेकर इस आरोप को स्वीकार कर लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर साथी दलों का बहुत ज्यादा दबाव था। दूसरे, विभागों के बंटवारे में भी देखें तो जिन्हें जो मिला उसे लेकर कम से कम सार्वजनिक स्तर पर किसी ने भी अपना असंतोष प्रकट नहीं किया है। ज्यादातर का बयान यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व की शीर्ष शक्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

गठबंधन सरकारों में साथी दलों के नेता इस तरह बेहिचक प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते थे। तीसरे, इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है, शीर्ष मंत्रालयों में फेरबदल न होना। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय , विदेश मंत्रालय यहां तक कि शिक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय आदि उन्हीं वरिष्ठ मंत्रियों के हाथ में है। सरकार गठन के पहले मीडिया में साथी दलों द्वारा अलग-अलग मंत्रालयों के मांग की अटकलें आ रही थी, जिनमें बिहार द्वारा रेल मंत्रालय की मांग शामिल थी।

वायु प्रदूषण से होती लाखों मौतों के लिये कौन जिम्मेदार?

कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। देश की हवा में घुलते प्रदूषण का 'जहर' अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिन्ता का बड़ा कारण हैं। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हो रही है।

यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जीवन-शैली ऐसी बन गयी है कि आदमी जीने के लिये सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया, इस गंभीर होती स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' की साझेदारी में जारी रिपोर्ट ने बयां किया है, इस रिपोर्ट के आंकड़े परेशान एवं शर्मसार करने के साथ चिन्ता में डालने वाले हैं, जिसमें वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। ज्यादा दुख की बात यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं थी। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्यथित, चिन्तीत व परेशान करने वाले हैं। वहीं सरकार के नीति-नियंताओं के लिये यह शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म आती ही कहा है? तनिक भी शर्म आती तो सरकारें एवं उनके कर्ता-धर्ता इस दिशा में गंभीर प्रयास करते। सरकार की नाकामयियां ही हैं कि जिन्दगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर उसे कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।

जानलेवा वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया के लिये एक गंभीर समस्या है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की कुल संख्या का प्रश्न है तो यह करीब 81 लाख बतायी जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसदी है। जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन-प्रशासन की कोताही एवं लापरवाही को ही दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि किन प्रमुख कारणों से वह प्रदूषण फैला रहा है और किस तरह वे इस जानलेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोगी हो सकते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसकी जीवनशैली वायु प्रदूषण को इतना बेपरवाह होकर क्यों फैलाती है? क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? देश की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है। विडम्बना तो यह है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें इस विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करती है, जानबूझकर प्रदूषण फैलाती है ताकि एक-दूसरे की छीछालेदर कर सके। प्रदूषण के नाम पर भी कोरी राजनीति का होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्थिति में बना रहना चिन्ता में डालता है। हालत ये बनते हैं कि कभी-कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं होता है। पराली के बाद पटाखों का धुआं भी बड़ी समस्या है, इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन, गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले में होना, उद्योगों की घातक गैसों व धुएं का नियमन न होने एवं बढ़ता धूम्रपान जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आवासीय कॉलोनियों व व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञानसम्मत ढंग से निर्माण न हो पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक वजह है। यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है? यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहां तनाव-ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है।

यूनीसेफ की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से 1 लाख 69 हजार बच्चे जिनकी औसत आयु पांच साल से कम बतायी गई है, मौत के शिकार होते हैं। जानलेवा प्रदूषण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होने से बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं, इनका समुचित शारीरिक विकास सही ढ़ंग से नहीं हो पाता। इससे बच्चों का कम वजन का पैदा होना, अस्थमा तथा फेफड़ों की बीमारियां से पीड़ित होना हैं। हमारे लिये चिंता की बात यह है कि बेहद गरीब मुल्कों नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से ज्यादा बच्चे हमारे देश में वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के संकट ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या को बढ़ाया ही है। एक अरब चालीस करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के लिये यह संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गयी है। हर कुछ समय बाद अलग-अलग वजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' की श्रेणी में दर्ज किया जाता है और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय करने की घोषणा की जाती है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन सच यह है कि फिर कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही है? इस विकट समस्या से मुक्ति के लिये ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर वायु प्रदूषण की गंभीर मार झेलते हैं।

सेट पर रूपाली गांगुली ने जमकर बजाया ढोल

टीवी सीरियल अनुपमा ने रूपाली गांगुली को स्टार बना दिया है। इस सीरियल में अनुपमा यानी रूपाली गांगुली हमेशा ही रोती हुई नजर आती हैं। शो में उनकी कई घरवालों से बनती नहीं है, लेकिन सेट पर असल जिंदगी में रूपाली गांगुली धमाल मचाकर रखती हैं। एक्ट्रेस सेट से अक्सर अपनी मस्ती भरी फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं, जिसमें वह अपने को-स्टार्स संग ठुमके लगाती हुई दिखी हैं। वहीं अब रूपाली ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनका गुजराती स्टाइल देख फैंस दीवाने हो गए हैं। इन फोटोज पर एक्ट्रेस के ऑनस्क्रीन बेटे आशीष मेहरोत्रा ने भी मजेदार कमेंट किया है।रूपाली गांगुली ने अपने सीरियल के सेट से कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह गुजराती लुक में कहर ढा रही हैं।रूपाली गांगुली ने इस तस्वीर में बंधेज की साड़ी पहनी हुई है, जो राजस्थान और गुजरात में ज्यादा पहनी जाती है। इस फोटो में वह नीचे देखकर पोज दे रही हैं, जिसमें एक्ट्रेस के बाल लहरा रहे हैं।सेट पर रूपाली गांगुली ने बजाया ढोलरूपाली गांगुली ने सेट से ढोल के साथ भी एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वह ढोल को इस तरह से गले में डाले हुए हैं, जैसे वह खुद ही ढोल को बजा रही हैं। रूपाली गांगुली ने इस तस्वीर में चश्मा पहनकर अपना टशन दिखाया है। वह फोटो में काफी सुंदर लग रही हैं और फैंस का ध्यान भी इस फोटो पर अटक गया है।रूपाली गांगुली की ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। कई फैंस ने रूपाली को बहुत सुंदर और पटाखा जैसे नाम से पुकारा है।

प्रभास की सीटी मार एंट्री ने हिलाए थिएटर्स

प्रभास की फिल्म कल्कि 2898.ष लंबे इंतजार के बाद आज यानी 27 जुलाई को धमाकेदार अंदाज में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दिग्गज कलाकारों से सजी इस फिल्म में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिशा पाटनी, कमल हासन, अमिताभ बच्चन समेत कई कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में साइंस फिक्शन के साथ एक्शन से भरी कहानी दिखाई गई है, जिसमें इंडियन आर्मी को भी जोड़ा गया है। अब नाग अश्विन और प्रभास की जोड़ी क्या दर्शकों पर कमाल कर पाएगी? आइए आपको इसके क्विक रिव्यू से बताते हैं, जिसमें आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ का पूरा ज्ञान मिल जाएगा।प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी (चढ्डद्यद्म 2898.ष) काल्पनिक दुनिया की शानदार कहानी है, जिसमें पौराणिक कथाओं के साथ-साथ मॉर्डन कल्चर देख दर्शक हैरान होने वाले हैं।

शानदार है फिल्म का फर्स्ट हाफ, थ्रिलर देख भूलेंगे हॉलीवुड

इस फिल्म में प्रभास भैरव के रोल में है, जिनकी एंट्री के लिए फैंस को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। प्रभास की एंट्री से दर्शकों ने बेशक काफी उम्मीदें लगाई होंगी और एक्टर इस पर खरे भी उतरे हैं। फिल्म में थोड़े इंतजार के बाद प्रभास एकदम सीटी मार एंट्री करते हैं और फिल्म में बाकी कलाकार जैसे दीपिका पादुकोण (सुमति), कमल हासन (यास्किन), अमिताभ बच्चन (अश्वत्थामा) समेत कई कलाकारों की एंट्री होती है। इन सभी कलाकारों की एंट्री दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में लेकर जाने का काम करेगी। फिल्म बेशक थोड़ी धीमी चलेगी, लेकिन इंटरवल तक आप लोगों को काफी मजा आने वाला है।फिल्म कल्कि 2898 एडी को बड़े लेवल पर बनाया गया है। फिल्म का स्क्रीन एक्सपीरियंस लाजवाब है और तमाम कलाकारों को इतने शानदार अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म की स्टोरी और ज्यादा रोमांचक बन जाती है।

इब्राहिम ने पलक के फोटो पर किया कमेंट

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की तरह ही उनकी बेटी पलक तिवारी भी आज इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। पलक ने बेहद कम उम्र में अपना नाम कमाया है। वो कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ पलक पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बीटाउन में पलक और इब्राहिम अली खान की दोस्ती की काफी चर्चा है। दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है। वहीं, सोशल मीडिया पर भी स्टार किड्स एक दूसरे की तस्वीरों पर खुलकर कमेंट्स करते हैं। इसी बीच एक अब इब्राहिम ने पलक की तस्वीर पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया कि लोग कह रहे हैं उनका रिश्ता तय होने की बात कर रहे हैं। एक्ट्रेस पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में हमेशा ही तरह ही पलक बेहद हॉट एंड गॉर्जियस नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें पलक के वेकेशन के दौरान की हैं, जिसमें वो फुल ऑन मस्ती करती दिख रही हैं। इन तस्वीरों में पलक ने ग्रीन कलर की फुल स्लीव्स टॉप के साथ ग्रे कलर का लोअर पहने नजर आ रही हैं। इस दौरान पल के खुले बाल और उनकी स्माइल ने न सिर्फ फैंस का बल्कि इब्राहिम अली खान का भी दिल चुरा लिया है। इब्राहिम ने किया ऐसा कमेंट- इब्राहिम अली खान, पलक तिवारी की इन तस्वीरों को देखकर खुद को कमेंटकरने से रोक नहीं पाए। इब्राहिम ने कमेंट करते हुए लिखा अच्छी लग रही हो। इब्राहिम के इस कमेंट पर पलक ने सरप्राइज वाली इमोजी बनाकर शेयर किया। इब्राहिम के इस कमेंट के बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी टांग खींचनी शुरू कर दी। इस पर कमेंट कर कई यूजर्स ने इब्राहिम को पहले अपने करियर पर फोकस करने की सलाह दी। तो कई ने कहा कि इन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। वहीं, कई ने पूछा कि क्या रिश्ता पक्का हो गया। इस तरह के कई और कमेंट्स पलक की इन तस्वीरों पर आ रहे हैं।

फरीदा जलाल बोलीं- मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया

एक न्यूज चैनल संग बातचीत में फरीदा जलाल ने कहा था कि शाहरुख खान ने शायद फोन नंबर बदल लिया है और नया नंबर मेरे पास है नहीं. इसलिए हम दोनों के बीच बात बंद हो गई है.

बीते दिनों एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने कहा था कि शाहरुख खान से उनका कनेक्शन खत्म हो चुका है. दोनों ही टच में नहीं. पर जब उनके इस स्टेटमेंट की चर्चा हर ओर होने लगी तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला गया. मेरे कहने का मतलब कुछ और ही था. इंडिया टुडे संग बातचीत में फरीदा जलाल ने कहा था कि शाहरुख खान ने शायद फोन नंबर बदल लिया है और नया नंबर मेरे पास है नहीं. इसलिए हम दोनों के बीच बात बंद हो गई है. दोनों का टच टूट गया है. अब जूम संग बातचीत में फरीदा ने अपने स्टेटमेंट में जौर देते हुए कहा कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया. अपने पुराने स्टेटमेंट को दोहराते हुए उन्होंने कहा- मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो शाहरुख खान का फोन नंबर आज के समय में मेरे पास है वो शायद बदल चुका है. मैंने बस इतना ही कहा था. मेरे से जो सवाल हुआ, उसका मैंने बहुत कम शब्दों में जवाब दे दिया था. मुझे इस बात का बुरा लगा कि मेरे स्टेटमेंट का मतलब लोगों ने ये निकाला कि मैं शाहरुख के लिए कह रही हूं कि उनमें पहले वो जब यंग थे तो थोड़े कच्चे थे, पर अब वो समय के साथ काफी निखर चुके हैं. मैं तो ये कहती हूं कि वो बेस्ट हैं अभी के लिए.卐 बता दें कि फरीदा और शाहरुख ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. इसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), डुप्लीकेट (1998), कुछ कुछ होता है (1998) और कभी खुशी कभी गम (2008)शामिल हैं. हाल ही में फरीदा जलाल को वेब सीरीज हीरामंडी में देखा गया था. इनके साथ मनीषा कोयराला, सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, अदिति राव हैदरी ने स्क्रीन शेयर की थी।

शादी के दो साल बाद मां बनने वाली हैं 'गोपी बहू'

दरअसल, टीवी की गोपी बहू ने हाल ही में बीच से अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। एक्टिंग के अलावा देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। पने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।इन तस्वीरों में देवोलीनाबीच पर अपने बालों को लहराते हुए कैमरे के लिए पोज देती नजर आईं। देवोलीना ने अपने ग्लैमरस लुक को खुले बालों और मैचिंग इयररिंग्स से पूरा किया है। लेकिन अब लुक से ज्यादा एक्ट्रेस तस्वीरों में दिख रहे अपने बेबी बंप को लेकर चर्चा में हैं।दरअसल इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बेबी बंप उनकी टाइट फिट ड्रेस में साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ कुछ यूजर एक्ट्रेस पर कमेंट कर पूछ रहे हैं कि %क्या आप प्रेग्नेंट हैं.. तो वहीं कुछ यूजर्स ने एक्ट्रेस को बधाई देना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, बहुत-बहुत बधाई दीदी।

10 जुलाई तक घर-घर जाकर योग्य लाभुकों को प्रेरित करें फ्रंट लाइन वर्कर्स : बीडीओ

- ➩ बक्सर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सहयोगी संस्थानों के साथ की बैठक
- ➩ अभियान में आशा कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी सेविकाएं, जीविका दीदी, विकास मित्र की भूमिका अहम

बक्सर (संवाददाता)।

जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्य से गुरुवार से मिशन परिवार विकास अभियान की शुरुआत हो गई। जिसके तहत 27 जून से 10 जुलाई तक सामुदायिक उत्प्रेरण पखवाड़ा का संचालन किया जाएगा। इस क्रम में सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित मिश्रा ने प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सभी सहयोगी संस्थानों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि समुदायिक उत्प्रेरण पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य योग्य लाभुकों को परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों के इस्तेमाल के साथ स्थायी साधनों के प्रयोग को लेकर प्रेरित करना है। जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाएं, जीविका दीदियां व विकास मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इनके माध्यम से लाभुकों को विशेषकर पुरुषों को नियोजन के स्थायी साधन के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया जाए। ताकि, अभियान को सफल बनाया जा सके।

विभिन्न गतिविधियों का करें संचालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि प्रखंड के पंचायतों व ग्राम स्तर पर लोगों को सामूहिक स्तर पर जागरूक किया जाए। जिसमें आशा, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, विकास मित्र आदि की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान आम जनों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने, बहु-बेटी सम्मेलन के आयोजन आदि का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि योग्य दंपतियों को उत्प्रेरित कर के पूर्व पंजीयन गर्व निरोधक सामग्रियां का वितरण सुनिश्चित करने के अलावा बंध्याकरण, नसबंदी आदि के कार्य अनिवार्य रूप से कराएं। साथ ही, लोगों को सही उम्र में शादी के कम से कम दो साल के बाद पहला बच्चा, दो बच्चों में तीन साल का अंतर तथा अन्य परिवार कल्याण से संबंधित जानकारी भी दी जाए, ताकि लोगों की जानकारी इस संबंध में बढ़ सकें।

11 जुलाई को मनाया जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस: बैठक में सदर प्रखंड के स्वास्थ्य प्रबंधक प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को सदर प्रखंड समेत पूरे जिले में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। जिसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग ने 27 जून से 10 जुलाई तक सामुदायिक उत्प्रेरण पखवाड़ा तथा 11 से 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का थीम विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दम्पति की शान है।

इस अभियान में गर्भ निरोधक, आपातकालीन स्थायी व अस्थायी उपाय एवं परामर्श सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही, जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना तथा योग्य दंपतियों को इच्छित सेवा प्रदान किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय बैठक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, बीपीएम जीविका, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

खबर-खास

फरार बारुपुर के बीडीसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बक्सर (संवाददाता)। राजपुर थाना क्षेत्र के बारुपुर पंचायत के बीडीसी अलीशेर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञात हो की पिछले 13 जून को अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी के ऑफिस में घुसकर बीडीसी अलीशेर शाह ने हंगामा कर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया था एवं सीओ के साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। जिस मामले को लेकर सीओ डॉक्टर शोभा कुमारी के द्वारा उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस मामले में पुलिस तलाश कर रही थी। तब से यह फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर उनके घर पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सीओ ने पुलिस को अवगत कराया था कि वह जनता की समस्याओं को सुनकर उनके कार्यों का निष्पादन कर रही थी। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात को रखा गया था। जिसको वह शालीनता के साथ समझा रही थी। इसी दौरान बीडीसी अलीशेर शाह बगैर अनुमति के उनके कार्यालय में पहुंचकर अपने आप को जनप्रतिनिधि का धौंस दिखाते हुए उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जिसका सीओ ने विरोध किया। इसी बात को लेकर काफी हंगामा हो गया। जहां कुछ देर के लिए अंचल कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अंचल कर्मी अपना कार्य छोड़ कार्यालय के पास पहुंच गए। अंचल गार्ड भी पहुंच कर शांति व्यवस्था को काम किया। जिस मामले में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं कर्मियों ने सुलझाने का प्रयास किया था। बात नहीं बन पाई थी। तब तक दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि इन पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है जिन्हें जेल भेंजा गया।

पूरे जिले में इधर से उधर हुये 57 लिपिक

बक्सर (संवाददाता)।

चुनाव समाप्ति के बाद डीएम अंशुल अग्रवाल ने 57 लिपिकों को इधर से उधर किया है। लंबे समय से जिला मुख्यालय में जमे लिपिको को प्रखंड में भेजा गया है।

डीएम ने जारी आदेश के तहत अजीत कुमार सिन्हा को जिला राजस्व शाखा से तबादला करते हुए डुमरांव अनुमंडल कार्यालय भेज दिया गया है। मुकेश कुमार सिन्हा को जिला पंचायत शाखा से नावानगर, तूफानी प्रसाद को विधि शाखा से अनुमंडल कार्यालय बक्सर, फैज अहमद को अंचल कार्यालय ब्रह्मपुर से जिला कल्याण कार्यालय बक्सर, मुक्ति नारायण पाठक को आईसीडीएस से अंचल कार्यालय चौगाईं, प्रवीण कुमार को जिला विधि शाखा से अंचल कार्यालय सिमरी भेजा गया है।

अनिल प्रसाद को अनुमंडल कार्यालय बक्सर से प्रखंड कार्यालय राजपुर, सुमन लाल को अनुमंडल कार्यालय डुमरांव से जिला विधि शाखा, असलम शाह को प्रखंड कार्यालय बक्सर से प्रखंड कार्यालय चौगाई, सुरेंद्र प्रसाद राम को प्रखंड कार्यालय नावानगर से जिला राजस्व शाखा, राधा प्रसाद साह को अंचल कार्यालय नावानगर से जिला राजस्व कार्यालय भेजा गया है। इसके साथ ही अन्य का भी स्थानांतरण किया गया है। वहीं दूसरी ओर डीएम ने नौ कार्यपालक सहायकों का भी स्थानांतरण किया है।

सफाई एजेंसी को लेकर नप अध्यक्ष ने जताया असंतोष, कहा - सफाई कर्मियों का जल्द करें भुगतान

बक्सर (संवाददाता)। आगामी मानसून को देखते हुए नगर निकाय क्षेत्रो मे जलजमाव होने को लेकर शुक्रवार को बैठक हुई। इस दौरान नगर के जितने जलजमाव के जगह है उन्हें चिन्हित कर उनका प्राकलन तैयार कर लिया गया है, वहीं सफाई एजेंसी के कार्यों को देखकर मुख्य पार्षद ने असंतोष जताया।

मुख्य पार्षद कमरू निशा ने बताया कि नगर विकास द्वारा दिए गए पत्र के आलोक नगर परिषद कार्यालय मे बैठक की जिसमे नगर के जितने जलजमाव के जगह है उन्हें चिन्हित कर उनका प्राकलन तैयार कर लिया गया। उनको बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से उन योजनाओं को नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा ताकि आगे का कार्य नगर विकास हो सके। वहीं सफाई एजेंसी सफाई कर्मचारियों के भुगतान मे देरी के चलते हड़ताल पर जाने से नगर की सफाई व्यवस्था चरमराई है। इस मामले कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया की कल तक सभी सफाई कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित करे अन्यथा एजेंसी पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। वहीं सफाई मित्रो से अनुरोध किया की आपका नगर है आप फिर से इसकी सफाई व्यवस्था बहाल करे बहुत जल्द आपका भुगतान किया जायेगा।

वाहनों के लिए जल्द से जल्द पार्किंग स्थल चिन्हित करें

बक्सर (संवाददाता)। जिला मुख्यालय स्थित सदर अनुमंडल कार्यालय में बीते दिन शहर में यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने किया। उन्होंने सर्वप्रथम यातायात व्यवस्था को लेकर नगर परिषद के ईओ को निर्देश दिया कि रामरेखा घाट से पीपी रोड, नगर थाना से ज्योति चौक, ज्योति चौक से आंबेडकर चौक व ज्योति चौक से सिडिंकेट पुल तक शहर में प्रवेश करने वाले दो पहिया वाहन के लिए जल्द से जल्द पार्किंग स्थल चिन्हित करते हुए, इन रूटों पर वाहन पार्किंग बोर्ड व फ्लैक्शी प्रदर्शित कर दो पहिया वाहनों की पार्किंग कराने को निर्देश दिया। इसके अलावा टोईंग वैन की व्यवस्था कर पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा। ताकि शहर में जहां-तहां सड़कों पर खड़े दो पहिया व चार पहिया वाहनों सड़क से हटाया जा सकें।

बताया कि ई-रिक्शा चालकों का रूट निर्धारित नहीं होने से आए दिन शहर में जाम की समस्या बनी रहती है। जिसपर एसडीएम ने 30 जून तक ई-रिक्शा संघ से बातचीत कर ई-रिक्शा का रूट निर्धारित करने और साथ ही वाहन संख्या के साथ सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके बाद 01 जुलाई से विशेष अभियान चलाकर ई-रिक्शा चालकों की चेकिंग होगी। साथ ही गलत पाये जाने पर फाइन भी किया जायेगा।

10 दिन में 4 ही पुल गिरे हैं..., पुल हादसों पर तेजस्वी का तंज

पटना (संवाददाता)। बिहार में बीते दस दिनों में पुल गिरने की चार चार घटनाओं पर राजनीति चरम पर है। सत्ता पक्ष के नेता जहां हादसों जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं तो विपक्षी दल इन घटनाओं के लिए डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर हमला कर रहे हैं।

इस बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे है।

शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के अंदर बिहार में करोड़ों की लागत से निर्मित और निर्माणाधीन केवल 4 ही पुल गिरे है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी/NDA की सरकार है तो सत्ता पक्ष और उनका अभिन्न अंग गोदी मीडिया इसे भ्रष्टाचार तो कदापि ही नहीं कह सकते। डबल इंजन सरकार के पायलट अब कहेंगे कि शुक्र मनाओ कि 10 दिन में 4 ही पुल गिरे है, 10 तो नहीं गिरे है ना। ये पायलट यह भी कहेंगे कि पुल गिरने के दोषी तो विपक्ष और जनता है?

इससे पहले अररिया, सीवान और पूर्वी चंपारण में पुल गिरने की घटनाओं के बाद भी तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला था। बीते 23 जून को भी तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट डालकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर जोरदार जुबानी हमला बोला था।

कथा : श्रीराम की प्रथम कर्मभूमि है सिद्धाश्रम

बक्सर (संवाददाता)। सर्वजन कल्याण सेवा समिति की ओर से रामरेखाघाट स्थित रामेश्वरनाथ मंदिर में चल रहे श्रीलक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह नौ दिवसीय श्रीराम कथा के छठें दिन सिद्धाश्रम बक्सर की महत्ता का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। तब श्रीराम की उम्र 15 वर्ष थी। जब महर्षि विश्वामित्र उन्हें बक्सर लाए थे। महर्षि ने श्रीराम को बल अतिबला दो विद्याएं प्रदान कर ताड़का वध कराया। श्रीराम ने मारीच को समुद्र पार भेज दिया। सुबह का वध किया एवं अन्य राक्षसों को पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण से ऊपर आकाश में भेज दिया। बक्सर श्रीराम की कर्मभूमि है। श्रीराम ने सर्वप्रथम अलौकिक मानव का कर्म बक्सर में किया। एक वाण से तड़का एवं एक ही वाण से सुबह का वध और एक ही वाण से मरीच का सात योजन समुद्र पर प्रक्षेपण उस कालखंड का अपूर्व शौर्य था। जनकपुर प्रस्थान के मार्ग में ऋषि पत्नी जो शिला रूप में पड़ी थी। उनको चरण रज से उद्धार कर ऋषि लोक में भेजना श्रीराम को तीनों लोकों में अन्यतम बना दिया। जनक के दरबार में जो शक्तियां धनुष को हिला न सकी। उसे देखते देखते श्रीराम दो खंडों में विभक्त कर विश्व विजेता बन गए

केसठ में भव्य पूजन, प्रवचन व भंडारे के साथ रूद्रा यज्ञ संपन्न : प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत खरपुरा में चल रहा रूद्रा यज्ञ गुरुवार को संपन्न हो गया। इससे पहले श्रीराम कथा का आयोजन किया गया था। कथा में प्रवचनकर्ता की भूमिका परम पूज्य श्री जीयर स्वामीजी महाराज के शिष्य मोहनजी दास ने निभाई थी। उन्होंने श्रीराम कथा का रसपान श्रद्धालु श्रोताओं को कराया। कथा चार दिनों तक चला। कथा का समापन विधिवत आरती के साथ गुरुवार की देर शाम हुआ। साथ ही भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का नेतृत्व राम बिहारी पांडेय एवं गुड्डू पांडेय ने किया। जिसमें समस्त ग्रामीण व क्षेत्र के लोगों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया।

स्कूल में गुंडई; बेंच पर पिस्टल रखकर परीक्षा देने का वीडियो वायरल

हलसी डॉन और माफियाओं से भरे बिहार के एक हाई स्कूल में मासिक परीक्षा के दौरान दो लड़कों का पिस्तौल के साथ पेपर लिखने का वीडियो वायरल हो गया है। अपराध की दुनिया में पांव रखने वाले अधिकांश नौजवान हाई स्कूल में ही रास्ता भटकते हैं जब वो पैसे के चक्कर में अपराधियों के प्रभाव में आ जाते हैं। सरकारी विद्यालयों में इस समय मासिक परीक्षा चल रही है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के एक से एक कारनामे सामने आ रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में बेंच पर पिस्तौल रखकर पेपर लिखने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस में हड़कंप मचा है। पिस्तौल के साथ परीक्षा देने का वायरल वीडियो हलसी प्रखंड के कैंदी उच्च विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में परीक्षा के दौरान दो परीक्षार्थी के बीच डेस्क पर पिस्टल रखा हुआ है। आश्चर्य की बात है कि परीक्षा के दौरान पिस्टल बेंच पर रखने से लेकर उसका वीडियो बनाने तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी।

35 वां प्रांतीय समूह खेलकूद समारोह का हुआ भव्य आगाज

कबड्डी और खो-खो के लगभग 800 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग

बक्सर (संवाददाता)। शहर के अहिरौली स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के परिसर में भारती शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार पटना के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को तीन दिवसीय 35 वां प्रांतीय खो-खो, कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। जो 30 जून तक चलेगा।

इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर19 के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत कार्यवाह राजेंद्र ठाकुर, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, खेल संरक्षक ब्रह्मदेव प्रसाद एवं राजेश प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्जवलित, पुष्प अर्पित कर एवं नारियल फोड़कर किया। इसके बाद छात्र छात्राओं के तहत सरस्वती वंदना किया गया। अतिथियों का स्वागत एवं परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा ने किया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग संयोजक डा हनुमान प्रसाद अग्रवाल ने की। वही कार्यक्रम का संचालन विभाग प्रमुख वीरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रांत कार्यवाह ने कहा कि खेल कूद से खिलाड़ी संस्कारी और अनुशासित होते है। शारीरिक शिक्षा के बिना जीवन अधुरा है। सुचना का पालन, आज्ञा का पालन एवं समय का पालन करने से व्यक्ति जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। वही प्रदेश सचिव ने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही हमारा उद्देश्य है। विद्या भारती के तहत संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक और खेलकूद की शिक्षा भी दी जाती है। इसी कड़ी में यह प्रांतीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न विद्यालयों के आठ सौ खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम के पहले दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिता कराई गई। जो देर शाम तक चलता रहा। ज्ञात हो कि यह खेल प्रतियोगिता डे व नाईट हो रहा है। मौके पर विभाग प्रमुख उमाशंकर पोद्दार, गंगा प्रसाद, उमाशंकर पांडेय, विमल पांडेय, भोला केशरी, बीरेंद्र कुमार, पारस मिश्र, दीपक कुमार, जगदीश राम, राकेश पांडेय, प्रमोद कुमार, जैनेन्द्र कुमार, सुलेखा देवी, चंद्रशेखर कुमार, जीवन राठौर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

मेगा कैंप में डीएम ने 47 लाभुकों के बीच बांटे गए 3.81 करोड़ की ऋण राशि

बक्सर (संवाददाता)। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पीएमईजीपी और पीएमईजीपी 2 एवं पीएमएफएमई योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैम्प का आयोजन किया गया। इस दौरान ऋण वितरण कैम्प में पीएमईजीपी योजना अन्तर्गत कुल 21 लाभुकों को ऋण स्वीकृति एवं कुल शून्य लाभुकों को वितरण पत्र एवं पीएमएफएमई योजना अन्तर्गत कुल 26 लाभुकों को ऋण स्वीकृति एवं कुल 01 लाभुकों को वितरण पत्र जिलाधिकारी द्वारा वितरित किया गया हैं। कुल 47 लाभुकों को ऋण स्वीकृति एवं भुगतान किया गया। जिसमें कुल 3.81 करोड़ की राशि सन्निहित है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिकारी एवं बैंकर्स यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो ताकि रोजगार सृजन के साथ-साथ लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उन्होंने ने भावी उद्यमियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे अनुरोध किया की अपने साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार अवसर सृजित करें तथा जिला एवं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के साझेदार बनें। वर्त्तमान समय में शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना हो रही है। बक्सर जिला अन्तर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है तथा सड़क एवं रेल नेटवर्क से जुड़ा है। जिसके कारण यहाँ के उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लाभुक को क्रमशः 25 प्रतिशत, 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के लाभुक को क्रमशः 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान इस योजना अंतर्गत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-2 अन्तर्गत वैसे आवेदक जिन्होनें पीएमईजीपी-01 एवं मुद्रा ऋण योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया हो तथा तीन वर्षों से कार्यरत इकाइयाँ, जो टर्म लोन की आदायगी बैंकों को कर दिया हो। उन्हे 15 प्रतिशत अनुदान की दर से 1.00 करोड़ रू तक का ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के उद्योगों को 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10.00 लाख रू अनुदान प्रदान किया जाता है। शिविर में अतुल कुमार, सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर, अग्रणी बैंक प्रबंधक, बक्सर एवं सभी बैंको के जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक एवं विभिन्न योजनाओं के लाभुक उपस्थित मौजूद रहे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड़, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480